www.deshkiupasana.com

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्र

RNI NO - UPHIN/2022/86937

जौनपुर से प्रकाशित

देश की उपासना

देश के विकास में समर्पित समाज के सभी वर्गों के लिए

DKU LIVE

सब पर नज़र, सबकी ख़बर

वर्ष – 05 | अंक – 17 | जौनपुर, सोमवार, 31 अगस्त 2026 | सान्ध्य दैनिक (संस्करण) | पेज – 4 | मूल्य – 2 रूपये

संक्षिप्त खबरें

नेपाल–चीन सीमा पर बाढ़ और भूस्खलन में फंसे महाराष्ट्र के 43 तीर्थयात्री सुरक्षित लौटे

नई दिल्ली, (एजेंसी)। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए महाराष्ट्र के 43 श्रद्धालु नेपाल–चीन सीमा के तिमुरे इलाके में बाढ़ और भूस्खलन के बीच फंसने के बाद रविवार को सकुशल घर लौट आए। जिस होटल में ये यात्री ठहरे थे, वह पानी के तेज बहाव में बह गया था जिसमें कुछ कर्मचारियों की जान चली गई। महाराष्ट्र सरकार के आपदा नियंत्रण कक्ष और ठाणे जिला प्रशासन ने लगातार समूह की स्थिति पर नजर रखी थी। कैलाश मानसरोवर यात्रा के दौरान नेपाल–चीन सीमा के पास अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के बीच फंसे महाराष्ट्र के 43 तीर्थयात्री रविवार को वापस लौट आए। इनमें ठाणे के निवासी भी शामिल हैं। इन तीर्थयात्रियों ने रुद्र टूर एंड ट्रैवल्स के माध्यम से यात्रा की थी। चीन में प्रवेश करने के कुछ समय बाद ही वे तिमुरे सीमा क्षेत्र में फंस गए थे। एक तीर्थयात्री ने बताया कि बाढ़ में वह होटल बह गया, जहां वे ठहरे थे। उन्होंने कहा कि इस हादसे में होटल के कुछ कर्मचारियों की मौत हो गई। कल्याण के निवासी प्रकाश शांताराम माने ने मुंबई पहुंचने के बाद गहरी राहत महसूस की। उन्होंने कहा, "जब हमें पता चला कि जिस होटल में हमने कुछ देर पहले नाश्ता किया था, वह बह गया है, तो हम स्तब्ध रह गए।" उन्होंने बताया कि चीनी अधिकारियों के निर्देशों के बाद आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया गया, जिसके कारण दुनिया भर से आए तीर्थयात्री सागा में फंस गए। उन्होंने कहा कि कुछ तीर्थयात्रियों ने कल्याण के सांसद डॉ. श्रीकांत शिंदे के करीबी सहयोगी अभिजीत दारेकर से संपर्क स्थापित किया। यहां एक स्थानीय अधिकारी ने बताया कि महाराष्ट्र सरकार का आपातकालीन नियंत्रण कक्ष और ठाणे जिलाधिकारी कार्यालय लगातार इस समूह की स्थिति पर नजर रखे हुए था।

सीएम योगी ने दीं श्रीकृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं, बोले-सत्य, धर्म और कर्म के संदेश को जीवन में उतारें

लखनऊ, (संवाददाता)। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को प्रदेशवासियों को श्रीकृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं दीं। उन्होंने पाती के माध्यम से प्रदेशवासियों से भगवान श्रीकृष्ण के सत्य, धर्म, कर्म और लोकमंगल के संदेश को जीवन में उतारने और विकसित एवं गौरवशाली उत्तर प्रदेश के निर्माण का संकल्प लेने का आह्वान किया। सीएम ने कहा कि योगेश्वर श्रीकृष्ण का संपूर्ण जीवन लोक कल्याणकारी शासन की मूल भावना की प्रेरणा देता है। इसी भावना के अनुरूप प्रदेश सरकार समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को सम्मान और सुरक्षा देने के साथ गरीबी मुक्त उत्तर प्रदेश, प्रतिभासंपन्न व निपुण युवाओं को रोजगार, अन्नदाताओं को सहारा और बेटियों को बेटों के समान आगे बढ़ने का अवसर देने के लिए कार्य कर रही है। सीएम योगी ने कहा कि श्रीकृष्ण कुलीनता के नहीं, बल्कि समरसता के प्रतीक हैं। वह समाज के हर वर्ग के साथ खड़े रहे। द्वारकाधीश होते हुए भी सुदामा के आत्मीय मित्र बने रहे। उनकी मित्रता यह संदेश देती है कि सच्चे संबंध पद, प्रतिष्ठा और संपन्नता से नहीं, बल्कि आत्मीयता से बनते हैं। उन्होंने कहा कि समरसता, समानता और आत्मीयता आज के समाज की भी आवश्यकता है। सीएम ने कहा कि असत्य और अन्याय के अंधकार के बीच भगवान श्रीकृष्ण के रूप में सत्य और धर्म का प्रकाश प्रस्फुटित हुआ। उनकी बाल लीलाएं केवल आनंद देने वाली कथाएं नहीं हैं, बल्कि उनमें गहरे आध्यात्मिक संदेश छिपे हैं। माखन चोरी की लीला सहजता और निश्छलता, जबकि गोप–गोपियों के साथ उनकी आत्मीयता प्रेम और सामाजिक समरसता का संदेश देती है। कालिय नाग के दमन की लीला अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक है। सीएम योगी ने कहा कि श्रीकृष्ण का जीवन बताता है कि समाज की वास्तविक शक्ति सामूहिक सहकारिता में निहित है। गोवर्धन पर्वत धारण कर उन्होंने प्रकृति, पशुधन और कृषि आधारित जीवन के संरक्षण का संदेश दिया। गोवर्धन पूजा के माध्यम से यह भी बताया कि सामूहिक एकजुटता बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना करने की शक्ति देती है। हर युग के लिए प्रासंगिक है ।

भारत वित्त वर्ष 2027 में 7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करेगा – वित्त मंत्री सीतारमण

नई दिल्ली, (एजेंसी)। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को कहा कि कोविड–19 महामारी के बाद से बनी ग्रोथ की रफ्तार को जारी रखते हुए भारत के 2026–27 वित्त वर्ष में 7 प्रतिशत या उससे ज्यादा की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट बनाए रखने की उम्मीद है। भौगोलिक नक्शा खोजना अपनी अमेरिकी यात्रा के दौरान शिकागो में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अमेरिका–ईरान संघर्ष और होर्मुज जलडमरूमध्य के बंद होने के कारण पैदा हुई जियोपॉलिटिकल अनिश्चितताओं और सप्लाई–चेन में रुकावटों के बावजूद भारत अपनी ग्रोथ की रफ्तार बनाए रखेगा। म्ततवत सवंकपदह के. वित्त मंत्री ने कहा कि ग्लोबल अनिश्चितताओं पर लगातार नजर रखने और साथ ही भारत की अपनी जरूरतों को समझने की वजह से हम मुश्किल हालात में भी डटे रहे। जबकि कई देश पूरी तरह से परेशान हैं और उनके हिसाब–किताब गड़बड़ा गए हैं। उन्होंने कहा कि मिडिल ईस्ट में संघर्ष के कारण होर्मुज जलडमरूमध्य में रुकावट से शुरू में भारत को कच्चे तेल, पेट्रोलियम उत्पादों और फर्टिलाइजर जैसी जरूरी चीजों की सप्लाई पर असर पड़ा, लेकिन देश ने सप्लाई का रास्ता बदलकर स्थिति संभाल ली। वित्त मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें तेजी से बढ़ने के बावजूद सरकार ने किसानों के लिए फर्टिलाइजर की कीमतें नहीं बढ़ाई हैं और सब्सिडी जारी रखी है।

अभिषेक बनर्जी के पीए से पूछताछ का रिकॉर्ड उच्चतम न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार से मांगा

बंगाल, (एजेंसी)। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को पश्चिम बंगाल सरकार से कहा कि वह तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी के निजी सहायक (पीए) सुमित रॉय की पूछताछ से जुड़े रिकॉर्ड पेश करे। रॉय ने आरोप लगाया था कि जांच करने वालों ने जमीन हड़पने के कथित मामले में उनसे बहुत कम पूछताछ की थी। इसके अलावा, शीर्ष अदालत ने रॉय को गिरफ्तारी से मिली अंतरिम सुरक्षा अगली सुनवाई (सात सितंबर) तक के लिए बढ़ा दी प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ रॉय की उस अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें कलकत्ता उच्च न्यायालय के छह अगस्त के आदेश को चुनौती दी गई थी। उच्च न्यायालय ने साल्बोनी भूमि कब्जाने के मामले में रॉय को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद, छह अगस्त को ही शीर्ष अदालत ने इस मामले में रॉय की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान, रॉय की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने कहा कि पूरी पूछताछ की वीडियो रिकॉर्डिंग की गई थी और उनके मुवक्किल ने पूछे गए सभी सवालों के जवाब दिए थे। शंकरनारायण ने पहले दी गई इस जानकारी में सुधार किया कि रॉय ने चुप रहने के अपने अधिकार का इस्तेमाल किया था। उन्होंने कहा कि पीठ के समक्ष दाखिल एक अतिरिक्त हलफनामे से पता चलता है कि रॉय ने खुद के खिलाफ गवाही न देने के अधिकार का इस्तेमाल नहीं किया था और जांच में पूरा सहयोग किया था। हालांकि, उन्होंने आरोप लगाया कि जांच करने वालों ने रॉय से उस अपराध के बारे में कम सवाल पूछे, जिसकी जांच हो रही थी।

भारत-उज्बेकिस्तान के बीच 11 समझौते, 5 बड़ी योजनाओं का ऐलान

नई दिल्ली, (एजेंसी)। ताशकंद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी के बीच उज्बेकिस्तान और भारत के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। पीएम मोदी के दो दिवसीय दौरे पर भारत और उज्बेकिस्तान के बीच 11 ज्ञापन समझौते और 5 योजनाओं का ऐलान हुआ है।नए स्थान तलाशें विदेश मंत्रालय की ओर से साझा जानकारी के अनुसार, भारत सरकार और उज्बेकिस्तान की सरकार के बीच वर्ष 2026–30 के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम के आदान–प्रदान पर मुहर लगी।उज्बेकिस्तान के टर्मेज में स्थित फयाज टेपा और कारा टेपा के प्राचीन बौद्ध स्थलों के संरक्षण और जीर्णोद्धार के लिए भारत के विदेश मंत्रालय और उज्बेकिस्तान की सांस्कृतिक विरासत एजेंसी के बीच समझौता। भारत के संस्कृति मंत्रालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार एवं उज्बेकिस्तान के न्याय मंत्रालय

के तहत एजेंसी उजआर्काइव के बीच अभिलेखीय कार्य के क्षेत्र में सहयोग को लेकर समझौता ज्ञापन एक्सचेंज हुआ। आयुर्वेद और पारंपरिक चिकित्सा की अन्य प्रणालियों के क्षेत्र में सहयोग पर भारत सरकार और उज्बेकिस्तान की सरकार के बीच समझौता ज्ञापन फाइनल हुआ। भूविज्ञान और खनिज संसाधनों के क्षेत्र में सहयोग पर भारत के खान मंत्रालय और उज्बेकिस्तान के खनन उद्योग और भूविज्ञान मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन तय हुआ।पर्यटन के क्षेत्र में 2026–28 के लिए भारत के पर्यटन मंत्रालय और उज्बेकिस्तान की पर्यटन समिति के बीच सहयोग पर साझेदारी कार्यक्रम पर बात बनी। भारत के विदेश मंत्रालय के सुषमा स्वराज विदेश सेवा संस्थान और उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्रालय के विश्व अर्थव्यवस्था और कूटनीति विश्वविद्यालय में डिप्लोमैटिक अकादमी के बीच समझौता ज्ञापन हुआ। आर्थिक और वित्तीय संवाद के लिए भारत के वित्त मंत्रालय और उज्बेकिस्तान के अर्थव्यवस्था और वित्त मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन हुआ।पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में सहयोग पर भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और उज्बेकिस्तान की पारिस्थितिकी और जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय समिति के बीच समझौता हुआ।

3 लैंडफिल साइटों से 2.16 करोड़ टन कचरा साफ, 100 एकड़ जमीन मुक्त सीएम रेखा गुप्ता

नई दिल्ली, (एजेंसी)। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रविवार को कहा कि ओखला, भलस्वा और गाजीपुर में कचरे के पहाड़ों को हटाने के लिए सरकार के वैज्ञानिक तरीके से अब तक लगभग 2.16 करोड़ मीट्रिक टन कचरे का निपटान किया गया है और 100 एकड़ जमीन वापस हासिल की गई है। उन्होंने कहा कि इससे लैंडफिल के पास रहने वाले लोगों को साफ–सुथरा और बेहतर माहौल देने में मदद मिली है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि कचरे के पहाड़ सालों से दिल्ली के लोगों के लिए एक बड़ी समस्या बने हुए थे। उनकी सरकार ने इन्हें हटाने का वादा किया था और एक वैज्ञानिक रोडमैप, लगन और समय–सीमा के साथ काम करके उस वादे को पूरा करने की दिशा में कदम उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार ने न केवल मौजूदा कचरे के पहाड़ों को हटाने पर ध्यान दिया है, बल्कि भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा न बने, इसके लिए भी योजना बनाई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि ओखला में लगभग 70 लाख मीट्रिक टन कचरे का निपटान किया गया है, जिससे 35 एकड़ जमीन वापस मिली है। भलस्वा में लगभग 102 लाख मीट्रिक टन कचरे का निपटान किया गया और 45 एकड़ जमीन वापस हासिल की गई। उन्होंने कहा कि इसी तरह, गाजीपुर में लगभग 44 लाख मीट्रिक टन कचरे का निपटान किया गया, जिससे 20 एकड़ जमीन वापस मिली। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि कचरे के पहाड़ों को हटाने का काम सिर्फ कचरा हटाने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका इन इलाकों में रहने वाले लोगों की जिंदगी पर भी सकारात्मक असर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि जो लोग रोज इन इलाकों से गुजरते हैं, वे अब बेहतर माहौल देख सकते हैं, साथ ही आस–पास रहने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता में भी सुधार हो रहा है। साफ–सुथरा और बेहतर माहौल स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा देने में मदद करेगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में कचरे के पहाड़ों से इतनी बड़ी जमीन वापस हासिल करना एक बड़ी उपलब्धि है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गाजीपुर में कचरे के निपटान के बाद जो बेकार सामग्री (इनर्ट मटीरियल) मिली है।

टीवीके ने साथ नहीं दिया तो पद छोड़ देंगे दोनों मंत्री, कांग्रेस की धमकी

चेन्नई, (एजेंसी)। मिलनाडु के मंत्री एस. राजेश कुमार ने कांग्रेस और तमिलगा वेत्री कझगम (टीवीके) के बीच गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर टीवीके 2029 के लोकसभा चुनाव के लिए राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार स्वीकार नहीं करती है, तो कांग्रेस के दोनों मंत्री राज्य मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे देंगे। राजेश कुमार ने रविवार को कन्याकुमारी में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि कांग्रेस 2029 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को ही प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर समर्थन देगी। उन्होंने दावा किया कि राहुल गांधी देश के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस इस मुद्दे पर अपने रुख से समझौता नहीं करेगी। राजेश कुमार के साथ उच्च शिक्षा मंत्री पी. विश्वनाथन भी तमिलनाडु सरकार में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते हैं। तमिलनाडु में सत्तारूढ़ गठबंधन के सहयोगी टीवीके के कई मंत्री, विधायक और नेता मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय को 2029 के लोकसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पेश करने की वकालत कर रहे हैं। इसी बीच राजेश कुमार का बयान कांग्रेस और टीवीके के बीच मतभेद बढ़ने का संकेत माना जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर गठबंधन सहयोगी राहुल गांधी की उम्मीदवारी का समर्थन नहीं करता है, तो वह और पी. विश्वनाथन अपने मंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। कांग्रेस ने मई में विजय के नेतृत्व वाली टीवीके को सरकार बनाने के लिए समर्थन देने का फैसला किया था। इसके बाद कांग्रेस को राज्य मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व दिया गया।

सेक्टर-131 स्थित यमुना किनारे गढ़ी गांव में गौशालाओं के विकास और गोवंश संरक्षण पर संतों ने दिया जोर

ब्यूरो चीफ सत्य प्रकाश उपाध्याय

नोएडा। सेक्टर–131 स्थित यमुना किनारे गढ़ी गांव में रविवार को गौशालाओं के विकास, गोवंश संरक्षण एवं गोसेवा को लेकर संतों की मौजूदगी में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। संतों ने समाज से गौशालाओं के उत्थान में सक्रिय सहयोग करने और गोवंश की सुरक्षा एवं देखभाल को सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में निभाने का आह्वान किया। प्रेस वार्ता में संत माधव गिरी जी, यति महादेवानंद गिरी, अजीत बाबा दास, मनोज गिरी, राम गिरी, सुग्रीव गिरी, मुख्य महंत सहित अनेक संत मौजूद

रहे। संतों ने कहा कि गौशालाओं में गोवंश के लिए भोजन, स्वच्छता, चिकित्सा, पानी और सुरक्षित आवास जैसी मूलभूत सुविधाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यति महादेवानंद गिरी ने कहा कि गोवंश संरक्षण केवल किसी एक संस्था की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि समाज के प्रत्येक वर्ग की सामूहिक जिम्मेदारी है। वहीं संत माधव गिरी जी ने नोएडा में आवारा गोवंश की समस्या के समाधान और गौशालाओं को मजबूत बनाने पर जोर देते हुए लोगों से आर्थिक एवं सामाजिक सहयोग की अपील की। उन्होंने बताया कि समाज के सहयोग से गौशाला में गोवंश के भोजन, चिकित्सा और रखरखाव की व्यवस्थाओं में सुधार हुआ है तथा भविष्य में इसे और बेहतर बनाने का प्रयास किया जाएगा। कार्यक्रम में नोएडा प्राधिकरण की ओर से गोवंश के लिए उपलब्ध कराई गई भूमि का भी उल्लेख किया गया। संतों ने बताया कि गोसेवा और जनजागरूकता को बढ़ावा देने के लिए आगामी समय में नियमित कार्यक्रम एवं शोभायात्राएं आयोजित की जाएंगी। उन्होंने समाज से गौशालाओं के विकास में सहयोग कर गोवंश संरक्षण के अभियान को मजबूत बनाने का आह्वान किया।

हरीश द्विवेदी के स्वागत में उमड़ा जनसैलाब, रुदौली विधायक रामचंद्र यादव,पूर्व विधायक इंद्र प्रताप तिवारी उर्फ खब्बू तिवारी सहित अन्य भाजपा नेताओं ने ऐतिहासिक भीड़ जुटाकर किया जमकर स्वागत

(राजन तिवारी सिटी रिपोर्टर)

अयोध्या। भाजपा के नवनियुक्त राष्ट्रीय महामंत्री हरीश द्विवेदी के प्रथम आगमन पर भव्य स्वागत समारोह का आयोजन किया गया।इस मौके पर रुदौली विधायक रामचंद्र यादव,गोसाईगंज के पूर्व भाजपा विधायक इंद्र प्रताप तिवारी उर्फ खब्बू तिवारी के नेतृत्व में हाईवे स्थित रौनाही टोल प्लाजा के पास हरीश द्विवेदी का जोरदार स्वागत किया गया।इसके अलावा अयोध्या नगर निगम के प्रथम महापौर ऋषिकेश उपाध्याय ने अन्य भाजपा के पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं के साथ उनका स्वागत किया।स्वागत समारोह में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता, समर्थक और स्थानीय लोग जुटे।भारी बारिश के बावजूद

कार्यकर्ताओं का उत्साह देखते ही बना। बारिश के बीच हजारों की संख्या में लोग हरीश द्विवेदी के स्वागत के लिए घंटों तक डटे रहे।इस दौरान हरीश द्विवेदी का करीब एक कुंतल वजन के फूलों के विशाल माले से माल्यार्पण किया गया। वहीं पूर्व विधायक गोसाईगंज इंद्र प्रताप तिवारी उर्फ के नेतृत्व में हजारों भाजपा कार्यकर्ताओं ने बुलडोजर के माध्यम से पुष्प वर्षा कर उनका भव्य अभिनंदन किया।जैसे ही हरीश द्विवेदी स्वागत स्थल पर पहुंचे, कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी और जयघोष के साथ उनका स्वागत किया।करीब दो से ढाई घंटे तक रौनाही टोल प्लाजा के आसपास कार्यकर्ताओं और समर्थकों का जबरदस्त सैलाब दिखाई दिया। बारिश के बीच भी लोगों में उत्साह कम नहीं हुआ। पूरे कार्यक्रम के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं में खासा जोश देखने को मिला।पूर्व विधायक खब्बू तिवारी ने हरीश द्विवेदी के स्वागत में कोई कोर–कसर नहीं छोड़ी। भव्य मंच, विशाल माला और बुलडोजर से पुष्प वर्षा ने स्वागत समारोह को खास बना दिया।हरीश द्विवेदी के स्वागत में उमड़ी भीड़ को लेकर राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा रही।खब्बू तिवारी के नेतृत्व में हुए इस भव्य आयोजन ने एक बार फिर अयोध्या में भाजपा कार्यकर्ताओं की सक्रियता और संगठन के प्रति उत्साह को सामने रखा।

संपादकीय

नेपाल की बाढ़ से सबक

नेपाल एक बार फिर बड़ी प्राकृतिक आपदा का शिकार हुआ है। यहां के रसुवा जिले और आसपास के नेपाल–चीन सीमावर्ती इलाकों में आई विनाशकारी बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। अब तक सैकड़ों लोगों की मौत और हजारों के लापता होने की खबरें हैं, लेकिन हताहतों की संख्या साफ–साफ बता पाना कठिन है। हर गुजरते वक्त के साथ मौतों का आंकड़ा बढ़ने की आशंका बनी हुई है। इस आपदा की चपेट में नेपाल का बड़ा हिस्सा आया है, लेकिन मरने और लापता होने वालों में कई विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। नेपाल पर्यटन बोर्ड के मुताबिक, लापता लोगों में भारत, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड्स, अमेरिका, मलेशिया, ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका के नागरिक शामिल हैं। भारत से बहुत से सैलानी कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नेपाल पहुंचे हुए थे, जिनकी अब कोई खबर नहीं है।26 अगस्त को आए इस प्रलय के जो वीडियो सामने आ रहे हैं, वो भयावह हैं। नदी का पानी विकरालता के साथ उमड़ता हुआ सबको लीलता हुआ आगे बढ़ रहा है। कहीं लोग जान बचाकर भाग रहे हैं, लेकिन फिर जलसमाधि लिए दिख रहे हैं, तो कहीं अपने घर की छतों पर खड़े होकर बचाव की गुहार लगा रहे हैं। चंद घंटों में ही सैकड़ों परिवार उजड़ चुके हैं। अपनी आंखों के सामने अपने परिजनों को बहते और डूबते देखने का दर्द आजीवन भुगतने के लिए सैकड़ों लोग अभिशप्त हो चुके हैं इस आपदा के बाद वैश्विक समुदाय की तरफ से नेपाल के लिए सहायता का हाथ बढ़ाया जा चुका है, जो सर्वथा सराहनीय है। भारत ने भी राहत सामग्री भेजने का सिलसिला शुरु कर दिया है। ऐसी आपदाएं सीमाओं में जकड़ी राजनीति और कूटनीति को एक पल ठहरकर सोचने का अवकाश देती हैं कि प्रकृति मनुष्य की बनाई सीमाओं को न जानती है, न मानती है। उसका कहर जब टूटता है तो धन, धर्म, भाषा, लिंग और देशों की सीमाओं की परवाह नहीं करता, सब एक जैसे इसमें प्रभावित होते हैं। इसलिए दुनिया पर अपना वर्चस्व दिखाने के लिए अतिक्रमण या घुसपैठ करना जिन देशों की फितरत रही है, उन्हें अपनी रणनीतियों पर विचार करना चाहिए। नेपाल की बाढ़ ने यह सवाल भी खड़ा किया है कि क्या यह वाकई प्राकृतिक घटना है या इसके लिए मनुष्य की गलतियां भी जिम्मेदार हैं। क्योंकि इस बाढ़ ने जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वॉर्मिंग के ज्वलंत सवालों को कुछ और सुलगा दिया है। जलवायु परिवर्तन के कारण ग्लेशियर्स काफी तेजी से पिघल रहे हैं। इसकी वजह से पहाड़ काफी कमजोर हो रहे हैं, क्योंकि जो बर्फ होती थी, वो एक तरह से सीमेंट का काम करती थी, यानी पहाड़ों को थामे रखना, मगर बर्फ तेजी से पिघल रहा है।

आरएसएस के सामने है खड़गे के सवालों की चुनौती

जगदीश रत्तनानी संघ के लिए हालात पहले से कहीं बेहतर हैं। उसकी गतिविधियां बढ़ रही हैं, सत्ता के गलियारों में संघ की चिंताओं को सुना और उन पर अमल किया जाता है। कई लोग आरएसएस को सरकार के कई फैसलों को आकार देने वाली एक ताकतवर शक्ति के तौर पर देखते हैं। संघ की सालाना रिपोर्ट में इसकी गतिविधियों के दायरे और संख्या का ब्यौरा तो मिलता है लेकिन पैसों का हिसाब–किताब नहीं बताया जाता। इसने प्रभाव के नए क्षेत्र भी बनाए हैं।राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) खुद मानता है कि वह एक बड़ा और दूर–दूर तक फैला हुआ संगठन है। आज देश भर में इसकी शानदार इमारतें और अच्छी तरह से बने हुए दफ्तर हैं। अपनी 100वीं सालगिरह पर संघ ने कई कार्यक्रम आयोजित किए। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक यादगार डाक टिकट तथा एक सिक्का भी जारी किया। संघ को भारतीय जनता पार्टी की वैचारिक जननीच कहा जाता है और भाजपा वही पार्टी है जिसने 2014 में सत्ता में आने के बाद से देश पर कड़ाई से शासन किया है। क्या ऐसे संगठन को बिना पर्याप्त पारदर्शिता, गवर्नेंस के ढांचे और लोगों को संगठित करने और देश के नागरिक जीवन के लगभग हर पहलू पर लोगों को प्रभावित करने के अपने तरीकों के बारे में जनता की जानकारी के बिना काम करना चाहिए?कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खड़गे ने संघ से बार–बार ऐसे ही सवाल पूछे हैं। ये सवाल संगठन के ढांचे, उसके अस्तित्व और उसकी पारा की जड़ तक जाते हैं। प्रधानमंत्री ने आरएसएस को श्दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओश कहा है। खड़गे ने पूछा है कि इतना बड़ा संगठन जब सार्वजनिक क्षेत्र में काम करता है, सार्वजनिक जगहों का इस्तेमाल करता है और बड़े पैमाने पर लोगों को इकट्ठा करता है, तो वह खुद को पंजीकृत क्यों नहीं कराता या अपना हिसाब–किताब क्यों जाहिर नहीं करता? ये आसान सवाल हैं लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण यह है कि ये वाजिब सवाल हैं।इस साल की शुरुआत में भेजे गए एक श्खुले पत्रश में खड़गे ने लिखा था कि संघ का श्लगातार लोगों को इकट्ठा करना... कानूनी स्थिति, जवाबदेही, आर्थिक स्थिरता, कानून–व्यवस्था, मंजूरी, फंडिंग के स्रोत और भारत के संविधान व कानूनों के पालन को लेकर जायज सवाल खड़े करता हैश्। आरएसएस ने इसके जवाब में कहा है कि रजिस्ट्रेशन तभी जरूरी होता है जब कोई संगठन सरकारी फंड लेना चाहता हो और हिंदू धर्म तो खुद भी रजिस्टर्ड नहीं है। लेकिन सबसे छोटे नॉन–प्रॉफिट या लेबर यूनियन को भी, जिसने कभी पब्लिक फंड का इस्तेमाल नहीं किया, रिकॉर्ड रखने और हिसाब–किताब जाहिर करने के लिए मजबूर किया जाता है। अगर संघ रजिस्टर्ड नहीं है तो वह मंजूरी के लिए कैसे आवेदन करता है, प्रशासन के साथ कैसे काम करता है और अपने प्रमुख के लिए जेड प्लस सुरक्षा कैसे हासिल करता है? इन सभी कार्यों में सार्वजनिक धन का इस्तेमाल होता है। यह हैरानी की बात है कि संघ संपूर्ण हिंदू आस्था के प्रतिनिधित्व करने का दावा करता है, उसे स्वयं अपने संगठन के बराबर मानता है। दोनों को एक मानने का मतलब है कि आरएसएस के बारे में पूछे गए किसी भी सवाल को धर्म के लिए चुनौती माना जाता है और कोई सवाल नहीं पूछा जाता। यह बेईमानी है और इससे संघ की अच्छी छवि नहीं बनती।संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि कानून के तहत आरएसएस को श्लोगों के एक समूहश के तौर पर पहचाना जाता है और इसे रजिस्टर कराने की कोई कानूनी मजबूरी नहीं है। यह बात संविधान के आर्टिकल 19(1)(सी) से जुड़ी है जो उचित पाबंदियों के साथ संगठन बनाने की आजादी देता है। 1994 के एक मामले के आधार पर टैक्स से छूट का दावा भी संघ करता है। उस मामले में पटना हाईकोर्ट ने एक सीमित बात पर फैसला सुनाया था कि श्आपसी सहभागिता का सिद्धांतश (प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअलिटी) के तहत संघ की किसी यूनिट को अपने सदस्यों से मिली गुरुदक्षिणा पर टैक्स नहीं लगेगा। टैक्स विभाग ने 1967–68 से 1975–76 तक के नौ सालों में आय की जो गणना की थी वह सालाना 15,000 रुपये से 71,000 रुपये के बीच थी जिससे यह एक छोटे एवं सीमित प्रभाव वाले संगठन जैसी दिखता था। उस मामले में रजिस्ट्रेशन का मुद्दा कोर्ट के सामने नहीं था और उसके बाद भी यह मुद्दा कभी नहीं उठा। कराधान की स्थिति का मुद्दा भी नहीं उठा। फिर भी, लचीलेपन और आनुपातिकता के आम तौर पर माने जाने वाले सिद्धांत यह बताते हैं कि जैसे–जैसे आकार बढ़ता है तथा ढांचा जटिल होता है, गवर्नेंस या कामकाज के नियम सख्त होने चाहिए। एक निश्चित आय सीमा से ऊपर वाले चैरिटेबल ट्रस्ट को अपने अकाउंट्स का ऑडिट कराना होता है, राजनीतिक दलों को एक सीमा से ज्यादा मिले दान की जानकारी देनी होती है तथा एक निश्चित सीमा से ऊपर वाली कंपनियों को अपने सीएसआर (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व) खर्च की रिपोर्ट देनी होती है।

15 दिनों के भीतर दो बार एक मंच पर आएंगे मोदी-पुतिन और शी, ट्रंप की बेचैनी बढ़ी

नीरज

भारतीय विदेश मंत्रालय ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एससीओ शिखर सम्मेलन में शिरकत करने की पुष्टि करते हुए उनके उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान दौरे के कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी जिसके बाद पूरी

दुनिया में हलचल–सी मच गयी है। हलचल इसलिए मची है क्योंकि जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग एक बार फिर एक साथ दिखाई देंगे, तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सीने पर पिछले साल की तरह फिर से सांप लोट सकते हैं। पिछली बार चीन के तियानजिन में एससीओ मंच पर इन तीन नेताओं की तस्वीर ने अमेरिकी रणनीतिक हलकों में बेचैनी बढ़ा दी थी। तब पूर्व अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने ट्रंप की टैरिफ नीतियों को भारत–अमेरिका रिश्तों को दशकों पीछे धकेलने वाला कदम बताया था और कहा था कि ऐसी नीतियों ने मोदी को पुतिन और शी के और करीब पहुंचा दिया। अब दृश्य और बड़ा है। पहले मध्य एशिया, फिर नई दिल्ली यानि पहले एससीओ और उसके तुरंत बाद ब्रिक्स। संदेश साफ है कि भारत किसी की रणनीतिक जागीर नहीं है। देखा जाये तो प्रधानमंत्री मोदी की उज्बेकिस्तान यात्रा और किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में 31 अगस्त से 1 सितंबर तक होने वाला एससीओ शिखर सम्मेलन ऐसे समय पर हो रहा है, जब मध्य एशिया वैश्विक शक्ति संघर्ष का नया मैदान बन चुका है। चीन बेल्ट एंड रोड के जरिए अपनी पकड़ बढ़ा रहा है, रूस इस क्षेत्र को अपने पारंपरिक प्रभाव क्षेत्र के रूप में देखता है और अमेरिका भी यहां अपनी मौजूदगी तथा रणनीतिक पहुंच बनाए रखने की कोशिश में है। ऐसे में मोदी की सक्रिय कूटनीति भारत को खेल का महत्वपूर्ण खिलाड़ी बना रही है। उज्बेकिस्तान इस रणनीति का अहम केंद्र है। मोदी की प्रस्तावित ताशकंद यात्रा व्यापार, रक्षा, निवेश, कनेक्टिविटी, डिजिटल तकनीक, ऊर्जा और महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नई गति दे सकती है। पिछले पांच वर्षों में भारत–उज्बेकिस्तान व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और द्विपक्षीय कारोबार लगभग 1.3 अरब डॉलर तक पहुंचने का उल्लेख किया गया है। भारत का निवेश फार्मास्यूटिकल्स, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में फैला है, जबकि भारतीय विश्वविद्यालय भी उज्बेकिस्तान में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं। लेकिन इस यात्रा की असली ताकत केवल व्यापार के आंकड़ों में नहीं है। उज्बेकिस्तान भारत की मध्य एशिया रणनीति का महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार है। पाकिस्तान द्वारा भूमि मार्ग अवरुद्ध रखने के कारण भारत के सामने संपर्क का प्रश्न लंबे समय से चुनौती बना हुआ है। यही वजह है कि अंतरराष्ट्रीय उत्तर–दक्षिण परिवहन गलियारा यानि आईएनएसटीसी और चाबहार बंदरगाह भारत के लिए सामरिक महत्व रखते हैं। ईरान और पश्चिम एशिया की मौजूदा अस्थिरता ने इन परियोजनाओं की राह कठिन जरूर बनाई है, लेकिन भारत के लिए विकल्प तलाशना अब मजबूरी नहीं, रणनीतिक आवश्यकता है। अफगानिस्तान भी मोदी–मिर्जियोयेव वार्ता का बड़ा मुद्दा हो सकता है। स्थिर अफगानिस्तान के बिना दक्षिण और मध्य एशिया की कनेक्टिविटी, व्यापार और सुरक्षा की कोई भी बड़ी योजना अधूरी है। ताशकंद और नई दिल्ली पुनर्निर्माण, आर्थिक विकास और क्षेत्रीय स्थिरता पर अधिक निकट समन्वय विकसित कर सकते हैं। इसके साथ ही रक्षा सहयोग, 'दुस्तलिक' सैन्य अभ्यास, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, विज्ञान–तकनीक और महत्वपूर्ण खनिजों में साझेदारी भारत की मध्य एशिया नीति को नई धार दे सकती है। इसके बाद बिश्केक में एससीओ का मंच मोदी को रूस और चीन समेत प्रमुख यूरेशियाई शक्तियों के साथ सीधे संवाद का अवसर देगा। भारत के लिए एससीओ केवल फोटो–ऑप नहीं है। आतंकवाद, ऊर्जा सुरक्षा, कनेक्टिविटी, आर्थिक सहयोग और क्षेत्रीय स्थिरता, ये सभी भारत के प्रत्यक्ष राष्ट्रीय हित से जुड़े प्रश्न हैं। नई दिल्ली लगातार यह भी रेखांकित करती रही है कि कनेक्टिविटी परियोजनाएं संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करें तथा आतंकवाद के खिलाफ दोहरे मानदंड स्वीकार नहीं किए जा सकते। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे दिलचस्प पहलू मोदी–पुतिन संबंध हैं। हम आपको बता दें कि विदेश मंत्री एस. जयशंकर की मॉस्को यात्रा के दौरान पुतिन ने मोदी से एससीओ में मिलने की इच्छा जताई और भारत के लिए उर्वरक आपूर्ति बढ़ाने की बात कही। दोनों देशों के बीच ऊर्जा, व्यापार, परमाणु सहयोग और कृषि जरूरतों से जुड़े रिश्ते लगातार महत्वपूर्ण बने हुए हैं। भारत ने पश्चिमी दबाव के बावजूद अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर रूस के साथ आर्थिक संबंध बनाए रखे हैं और यही मोदी की रणनीतिक स्वायत्तता का सबसे बड़ा प्रमाण है। लेकिन असली भू–राजनीतिक धमाका इसके बाद हो सकता है। 12–13 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में पुतिन और शी चिनफिंग की मौजूदगी की संभावना भारत की कूटनीतिक हैसियत को और मजबूत करेगी। यदि मोदी, पुतिन और शी एक ही मंच पर लगातार दो बड़े अंतरराष्ट्रीय आयोजनों में मिलते हैं, तो यह किसी औपचारिक मित्रता की घोषणा नहीं होगी लेकिन यह जरूर दिखाएगा कि विश्व राजनीति अब एकध्रुवीय निर्देशों पर नहीं चलती। भारत, रूस और चीन के बीच मतभेद मौजूद हैं, विशेषकर भारत–चीन संबंधों में। इसलिए इसे किसी स्थायी त्रिपक्षीय गठबंधन के रूप में देखना जल्दबाजी होगी। मगर बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था, वैश्विक शासन सुधार, ग्लोबल साउथ की आवाज, ऊर्जा सुरक्षा और वैकल्पिक आर्थिक संस्थाओं के सवाल पर तीनों देशों की बातचीत का प्रभाव अमेरिका और पश्चिमी शक्तियों तक जरूर पहुंचेगा। मोदी की उज्बेकिस्तान से बिश्केक और फिर नई दिल्ली तक फैली यह कूटनीतिक श्रृंखला एक बड़े संदेश का निर्माण करती है। संदेश यह है कि भारत अब मध्य एशिया में अपनी पहुंच बढ़ा रहा है, रूस के साथ पुराने रणनीतिक संबंधों को नए आर्थिक आधार दे रहा है, चीन के साथ प्रतिस्पर्धा और संवाद, दोनों को एक साथ साध रहा है और ब्रिक्स जैसे मंचों के जरिए ग्लोबल साउथ की राजनीति को नई दिशा देने की कोशिश कर रहा है। वॉशिंगटन के लिए संदेश इसलिए असहज हो सकता है, क्योंकि दबाव, टैरिफ और रणनीतिक ध्रुवीकरण की राजनीति भारत को किसी खेमे में बांधने की गारंटी नहीं देती। बहरहाल, मोदी की कूटनीति का मूल मंत्र साफ दिखाई देता है कि जहां भारत का हित, वहीं भारत का हाथ। अगले कुछ सप्ताह में ताशकंद, बिश्केक और नई दिल्ली के मंच शायद यही साबित कर दें कि बदलती विश्व व्यवस्था में भारत अपनी शर्तों पर चाल चलने वाला निर्णायक खिलाड़ी है।

मराठी अस्मिताबोध की नई अभिव्यक्ति

उमेश

महाराष्ट्र के ऑटो–रिक्शा और टैक्सी चालकों के लिए कामचलाऊ मराठी भाषा जरूरी किए जाने को लेकर विवाद उठना स्वाभाविक है। यह विवाद बांबे हाईकोर्ट भी पहुंच गया है। महाराष्ट्र सरकार ने इस नियम को लागू करते हुए तर्क दिया है कि इससे यात्रियों और टैक्सी–ऑटो चालकों के बीच भरोसा बढ़ेगा और यात्रियों में सुरक्षा का भाव रहेगा। मोटे तौर पर सरकार की यह दलील बेहतर लगती है, लेकिन जब राज्य की टैक्सियों और ऑटो की संख्या और उनके चालकों पर ध्यान देते हैं तो यह सवाल सिर्फ भाषा का नहीं रह जाता, बल्कि उपराष्ट्रीयता के उभार और उसके बहाने राष्ट्रीयता के विचार को चुनौती का भी हो जाता है। इस सोच का सिरा आगे बढ़ते हुए हिंदी विरोध और प्रकारांतर से पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के प्रवासियों की मुखालफत तक जा पहुंचता है। भारतीय राष्ट्रीयता के समर्थन में 'विविधता में एकता' का पाठ हर भारतीय को स्कूली घुट्टी में मिला है। लेकिन जीवन की कठोर राहों पर उतरते हैं तो पता चलता है कि राष्ट्रीयता की असल धारा जितनी गहरे तक हिंदी हृदय प्रदेशों में बहती है, उतनी गैर हिंदीभाषी प्रदेशों में नजर नहीं आती। दिलचस्प यह है कि राष्ट्रीयता के पुरजोर पोषक इन इलाकों को उपहास में कभी बीमारू कहा जाता था। इस पर गोबरपट्टी और गोबरनाडु का विशेषण खास धारा की वैचारिकी ने जो चस्पा कर रखा है। इस सोच की प्रमुख वजह आर्थिक रूप से इन इलाकों का अपेक्षाकृत उपराष्ट्रीयता वाले इलाकों से पिछड़े रहना है। इसी वजह से रोजी–रोटी की खातिर महाराष्ट्र के टैक्सी और ऑटो चालकों में सबसे बड़ी संख्या भदेस माने वाले बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश आदि के प्रवासी शामिल हैं। जाहिर है कि मराठी के कामचलाऊ ज्ञान रखने के नियम का शिकार यही लोग ज्यादा हुए हैं। इससे इनकी ही रोजी–रोटी पर संकट बढ़ा है। महाराष्ट्र के ताजा आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक, राज्य में 12 लाख 96 हजार से ज्यादा ऑटो हैं, जबकि करीब पांच लाख टैक्सियां हैं। यहां के परिवहन विभाग के मुताबिक, अकेले ग्रेटर मुंबई इलाके में करीब पांच लाख टैक्सियां और ऑटो रिक्शा चल रहे हैं। इनमें करीब 75 फीसद ऑटो–टैक्सी चालक गैर मराठी और हिंदीभाषी इलाकों के ही हैं। राज्य के दूसरे इलाकों में करीब आधे ऑटो–टैक्सी चालक हिंदीभाषी हैं। महाराष्ट्र ही क्यों, किसी भी राज्य के सेवा क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों को वहां की स्थानीय भाषा आनी चाहिए। उनके रोजाना का काम स्थानीय भाषा के कामचलाऊ ज्ञान से चल सकता है। बड़ा सवाल यह है कि मराठी के कामचलाऊ ज्ञान का पैमाना क्या हो, महाराष्ट्र सरकार का आदेश इस मसले में स्पष्ट नहीं है। विवाद और परेशानी इस वजह से भी है। सर्विस सेक्टर और रेहड़ी–पटरी लगाने वाले अक्सर कामकाज करते–करते स्थानीय भाषा सीख लेते हैं। दिल्ली के कनॉट प्लेस में हथकरघा और दस्तगारी का सामान बेचने वाली गुजराती महिलाएं कम शिक्षित हैं। लेकिन वे हिंदी ही नहीं, अंग्रेजी, जर्मन और स्पेनिश भी धाराप्रवाह बोल लेती हैं। तमिलनाडु को लेकर धारणा है कि वहां घोर हिंदी विरोधी माहौल है। लेकिन वहां के प्रमुख पर्यटन स्थल महाबलीपुरम् में भीख मांगने वाले भी बहुभाषी मिल जाते हैं, जो हिंदीभाषी सैलानियों से हिंदी में भीख मांगते हैं। वहां घूम–घूमकर छोटे–मोटे सामान बेचने वाली लड़कियां भी फर्राटेदार अनफाइ हैं, लेकिन वे हिंदी, गुजराती, बांग्ला आदि बोल लेती हैं। चाहे कनॉट प्लेस के फुटपाथ पर दस्तगारी का सामान बेचने वाली गुजराती महिलाएं हों या कोलकाता की गलियों में दुकान लगाने वाले बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग हों, अगर वे अंग्रेजी और बांग्ला आदि बोलते हैं तो इसकी वजह कोई स्कूली शिक्षा नहीं, बल्कि रोजाना का संपर्क और जरूरत है। ऐसा नहीं कि महाराष्ट्र के ऑटो–टैक्सी चालक मराठी का कामचलाऊ ज्ञान या समझ नहीं रखते। यहां ध्यान रखने की बात है कि अपनी माटी से दूर जब कोई ऑटो या टैक्सी चलाने का काम चुनता है तो वह तत्काल सड़क पर नहीं उतरता। वह पहले सड़कों को पहचानता है, उनकी भाषा को समझने की कोशिश करता है। भाषा विज्ञान की नजर से देखें तो मराठी, गुजराती और राजस्थानी ऐसी भाषाएं नहीं हैं, जिन्हें आम हिंदीभाषी समझ नहीं सकता। ठीक इसी तरह इन भाषा–भाषियों के लिए हिंदी भी ऐसी भाषा नहीं है, जिसे वे न समझ सकें। भाषा को लेकर जब भी कोई विवाद उठता है, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त टीएन शेषन का एक इंटरव्यू याद आता है। जिसमें उन्होंने अपनी दादी की चारधाम यात्रा का जिक्र किया था। उनकी दादी ने शायद पिछली सदी के दूसरे दशक में तमिलनाडुके पालघाट इलाके के अपने गांव से चारधाम की यात्रा की थी और महीनों बाद सकुशल वापस लौट आई थीं। शेषन ने कहा था कि उनकी दादी तमिल के अलावा कोई अन्य भाषा नहीं जानती थीं, लेकिन उन्हें चारधाम यात्रा से दिक्कत नहीं हुई। सिर्फ शेषन ही नहीं, सदियों से लोग भारत के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक तीर्थ यात्राएं करते रहे हैं। आज तो तकनीक का विस्तार हो गया है, संचार क्रांति हो चुकी है। जब ये सहूलियतें नहीं थीं, तब क्या तीर्थ यात्राएं रुकीं। तब क्या भाषाएं बाधा बनीं। ऐसे में सवाल यह है कि फिर आज भाषा कैसे चुनौती बन सकती है। कम ही लोग स्वीकार करेंगे, लेकिन राज्यों के पुनर्गठन के लिए बनाए गए फजलुर्रहमान आयोग की रिपोर्ट ही भाषायी उपराष्ट्रीयता को बढ़ावा देने वाली रही। आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश की थी। इसी के नजीतन भारतीय उपराष्ट्रीयताओं को अपनी भाषाओं के बहाने अपना वर्चस्व साबित करने का आधार मिल गया। इसी वजह से आए दिन राज्यों में अपनी भाषाओं को लेकर अस्मिताबोध जागता रहता है। इस बोध के निशाने पर अक्सर हिंदीभाषी ही रहते हैं। महाराष्ट्र सरकार में शामिल एकनाथ शिंदे की शिवसेना के मूल में भी मराठी उपराष्ट्रीयता और अस्मिताबोध रहा है। इस अस्मिताबोध को शिवसेना संस्थापक बाला साहब ठाकरे ने पहली अभिव्यक्ति 1960 के दशक में मुंबई में मलयाली भाषा–भाषियों के खिलाफ आंदोलन के जरिए दी और बाद के दिनों में उनके भतीजे राज ठाकरे तो इस अस्मिताबोध के दबंग पैरोकार बनकर उभरे। केंद्र सरकार और बैंकों आदि की नौकरियों के लिए परीक्षा देने मुंबई–नासिक आदि पहुंचे हिंदीभाषी छात्रों को बाकायदा पीटकर इस भाषा बोध को राज ठाकरे के कथित सैनिक दिखाते रहे।

टोक्यो ने चीन और दक्षिण-पूर्व एशिया को पीछे छोड़ते हुए भारत में भारी निवेश किया

गोपाल

जापानी निवेशक कम लागत वाले विनिर्माण और निर्यात के बजाय अपने निवेश के लिए घरेलू मांग पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। भारत की विकास दर ने वैश्विक आर्थिक तनाव (जो ट्रंप के ऊंचे टैरिफ के कारण पैदा हुआ) के बावजूद मजबूती दिखाई है और खर्च पर आधारित अर्थव्यवस्था के लिए एक नए खिलाड़ी के तौर पर उभरा है, जो श्नए भारतश की तस्वीर पेश करता है। जापानी येन की कीमत बढ़ने के बाद के दौर में, जापानी विदेशी निवेश कम लागत वाले विनिर्माण के लिए चीन और आसियान की ओर चला गया था, जिससे भारत पीछे छूट गया था। अब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के ऊंचे जवाबी टैरिफ की वजह से यह रुझान उलटी दिशा में चल पड़ा है। भारत में जापानी निवेश तेजी से बढ़ा है और इसने चीन और आसियान को पीछे छोड़ दिया है। जहां 2025 में भारत में जापानी निवेश 37.1 प्रतिशत बढ़ा, वहीं चीन और आसियान में इसमें क्रमशः 29.1 प्रतिशत और 48.9 प्रतिशत की गिरावट आई। बेफिक्र जापानी निवेशक कम लागत वाले विनिर्माण और निर्यात के बजाय अपने निवेश के लिए घरेलू मांग पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। भारत की विकास दर ने वैश्विक आर्थिक तनाव (जो ट्रंप के ऊंचे टैरिफ के कारण पैदा हुआ) के बावजूद मजबूती दिखाई है और खर्च पर आधारित अर्थव्यवस्था के लिए एक नए खिलाड़ी के तौर पर उभरा है, जो श्नए भारतश की तस्वीर पेश करता है। नेल्सन आईक्यू वर्ल्ड डेटा लैब की रिपोर्ट के अनुसार, अगले दशक में भारत अमेरिका के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा घरेलू बाजार बन सकता है। अपनी मौजूदा विकास दर के आधार पर यह चीन से आगे निकल जाएगा।भारत ने दुनिया में सबसे ज्यादा जीडीपी विकास दरों में से एक दर्ज की है, जो 2025–26 में 7.9 प्रतिशत रही। आने वाले वर्षों में भी इसी तरह की विकास दर दर्ज करने की उम्मीद है। इसकी उच्च जीडीपी विकास दर निर्यात के बजाय घरेलू मांग से प्रेरित थी, जिसका कारण इसकी भूजनसांख्यिकी बढ़त (युवा आबादी का लाभ) है। चीन की घरेलू खपत भारत से पीछे है, क्योंकि भारत में मध्यम आय वर्ग और अमीर आबादी का हिस्सा ज्यादा है। इसका मतलब है कि भारत में विदेशी निवेश के लिए एक नई गतिशीलता आई है, जो आसियान–10 और चीन से आगे निकल रही है। जहां भारत में जापानी निवेश का लक्ष्य घरेलू मांग और कम लागत वाली वैकल्पिक आपूर्ति श्रृंखला पर केंद्रित है, वहीं आसियान–10 में चीनी निवेश अमेरिका को सामान के निर्यात के लिए बढ़ा है।चीन की तुलना में आसियान पर अमेरिकी टैरिफ कम है। जहां चीनी सामानों से सीधे अमेरिकी निर्यात पर 47.5 प्रतिशत का अमेरिकी टैरिफ लगता है, वहीं आसियान सदस्य देशों के निर्यात पर टैरिफ 10 प्रतिशत से 49 प्रतिशत के बीच होता है। भले ही आसियान–10 सदस्य देशों के बीच टैरिफ में काफी अंतर है, लेकिन चीनी एफडीआई वाले सदस्य देशों में बने सामान पर अमेरिका को सीधे किए जाने वाले चीन के निर्यात की तुलना में कम टैरिफ लगता है।आसियान में चीनी निवेश मुख्य रूप से 4 सदस्य देशों में केंद्रित है। ये देश हैं– मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड और वियतनाम। वियतनाम को छोड़कर, बाकी तीन सदस्य देशों पर अमेरिका का पारस्परिक टैरिफ 24 से 36प्रतिशत के बीच है। यह चीन के निर्यात पर लगने वाले टैरिफ से काफी कम है। इससे आसियान में चीनी निवेशकों को सामान बनाने और उसे अमेरिका निर्यात करने का खास फायदा मिलता है। आखिरकार, अमेरिका के ऊंचे पारस्परिक टैरिफ के बावजूद 2024 और 2025 में आसियान से अमेरिका को होने वाले निर्यात में तेजी आई। भारत में जापानी निवेश का हालिया ट्रेंड निवेश के क्षेत्रों की दिशा में काफी बदलाव दिखाता है। ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, दवा और फार्मास्यूटिकल्स जैसे विनिर्माण क्षेत्र के बजाय वित्तीय सेवाओं में बड़ा निवेश किया गया। सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग, मिजुहो सिक्योरिटीज और एमयूएफजी बैंक का बड़ा निवेश इसके उदाहरण हैं। यस बैंक, एवेन्डस कैपिटल और श्रीराम फाइनेंस में उनके बड़े निवेश से भारत में जापानी निवेश की एक नई दिशा का पता चलता है, जिसमें ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, दवा और फार्मास्यूटिकल्स जैसे विनिर्माण क्षेत्र पीछे छूट गए हैं। एक आधिकारिक दस्तावेज के अनुसार, सेवा क्षेत्र में जापानी निवेश विनिर्माण क्षेत्र से आगे निकल गया। 2000 से 2025 के दौरान, भारत में कुल जापानी निवेश में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी 18.1 प्रतिशत थी, जिसके बाद ऑटोमोबाइल और अन्य क्षेत्रों का स्थान रहा। भारत में जापानी निवेश का वित्तीय सेवा की ओर झुकाव बढ़ने के कारणों में घरेलू उपभोक्ता बाजार का बढ़ना और उससे जुड़े बढ़े कर्ज बाजार का विकास शामिल है। जापानी वित्तीय संस्थान तेजी से भारत की स्थानीय नॉन–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) और निजी वाणिज्यक बैंकों के साथ जुड़ रहे हैं। उदाहरण के लिए, मित्सुबिशी यूएफजे फाइनेंस कॉर्पोरेशन (एमयूएफजी) ने रिटेल और व्हीकल कर्ज का विस्तार करने के लिए श्रीराम फाइनेंस में 20प्रतिशत हिस्सेदारी के लिए + 4.4 अरब का निवेश करने का वादा किया। सुमितोमो मित्सुई फाइनेंस ग्रुप ने यस बैंक में 24.2 प्रतिशत की बड़ी हिस्सेदारी हासिल करके सबसे बड़ा शेयर होल्डर बनने का मुकाम हासिल किया।जेटरो के एक सर्वे के अनुसार, भारत में 80.3 प्रतिशत जापानी निवेशक विस्तार करने पर विचार कर रहे हैं, जो सबसे अधिक है। इसके विपरीत, थाईलैंड में व्यापार विस्तार की इच्छा में कमी आई और चीन में यह रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गई। सर्वे से पता चला है कि जापानी निवेशकों के लिए मुनाफा कमाने के मामले में भारत तीसरे नंबर पर है, और इससे बाद दक्षिण कोरिया और ताइवान का स्थान है। जापानी निवेश को आकर्षित करने में भारत ने आसियान–10 देशों को पीछे क्यों छोड़ दिया है, जबकि जापान दुनिया के सबसे बड़े फ्री ट्रेड ब्लॉक आरसीईपी (रीजनल कोऑपरेशन ऑफ इकानॉमिक पार्टनरशिप) का सदस्य है? भारत आरसीईपी का सदस्य नहीं है। इसके पीछे जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की दूरदर्शिता का अहम योगदान है, जिन्होंने दक्षिण–पूर्व एशिया में चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के लिए यह पहल की थी। जापान के ऐतिहासिक और राजनीतिक संबंध चीन के साथ विवाद के कारण जापान, अमेरिका, भारत और ऑस्ट्रेलिया की सदस्यता वाला एफओआईपी (फ्री एंड ओपन इंडो–पैसिफिक) बना। इसका मकसद चीन की बढ़ती ताकत को संतुलित करना है। इसलिए, जापान के दिवंगत प्रधानमंत्री शिंजो आबे की दूरदृष्टि की विरासत भारत–जापान संबंधों का मुख्य आधार बनी हुई है।

स्वाइन फ्लू को लेकर अनावश्यक भय न फैलाएं-सतर्क रहें, घबराएं नहीं - प्रो. डॉ. आर. बी. कमल

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर,। प्रदेश में स्वाइन फ्लू से संबंधित मामलों की जानकारी के बाद जनसामान्य में बढ़ती चिंता को देखते हुए उमानाथ सिंह स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, जौनपुर प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि स्वाइन फ्लू को लेकर अनावश्यक भय अथवा अफवाहों पर ध्यान न दें। सतर्कता, प्रमाणित जानकारी, समय पर चिकित्सकीय परामर्श एवं आवश्यक सावधानियों के माध्यम से संक्रमण के प्रसार को प्रभावी रूप से नियंत्रित किया जा सकता है। चिकित्सा–महाविद्यालय प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्थिति की निरंतर निगरानी एवं समीक्षा की जा रही है। मरीजों के चिकित्सकीय मूल्यांकन, आवश्यक जांच, उपचार एवं निगरानी के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सक्रिय रखी गई हैं तथा किसी भी संभावित स्थिति से निपटने के लिए संबंधित चिकित्सा एवं सहायक सेवाओं के बीच समन्वय सुनिश्चित किया जा रहा है। प्रो. डॉ. आर. बी. कमल, प्रधानाचार्य, उमानाथ सिंह स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, जौनपुर ने जनसामान्य को आश्वस्त करते हुए कहा कि 'स्वाइन फ्लू को लेकर किसी भी प्रकार की अनावश्यक घबराहट की आवश्यकता नहीं है।' उन्होंने कहा कि संस्थान स्थिति पर सतत नजर रख रहा है तथा उपलब्ध चिकित्सा संसाधनों, मानव संसाधन और आवश्यक व्यवस्थाओं की नियमित समीक्षा की जा रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि स्वास्थ्य संबंधी किसी भी आकस्मिक स्थिति में संस्थान की सर्वोच्च प्राथमिकता मरीजों को समय पर उचित एवं गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना है। प्रो. डॉ. कमल ने कहा कि बीमारी से संबंधित भय और अपुष्ट सूचनाएं जन–चिंता को बढ़ा सकती हैं। इसलिए आमजन केवल 'स्वास्थ्य विभाग, सरकारी चिकित्सा संस्थानों एवं अधिकृत चिकित्सा विशेषज्ञों द्वारा जारी प्रमाणित जानकारी' पर विश्वास करें। सोशल मीडिया पर प्रसारित किसी भी अपुष्ट संदेश, वीडियो या पोस्ट को बिना सत्यापन के आगे साझा न करें। उन्होंने कहा कि जागरूकता और जिम्मेदार स्वास्थ्य व्यवहार संक्रमण नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रो. डॉ. ए. ए. जाफरी, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक ने बताया कि अस्पताल में स्वाइन फ्लू एवं अन्य श्वसन संबंधी संक्रमणों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक चिकित्सा सुविधाओं एवं व्यवस्थाओं की नियमित समीक्षा की जा रही है। आने वाले मरीजों का चिकित्सकीय मूल्यांकन किया जा रहा है तथा आवश्यकता के अनुसार जांच, उपचार एवं निगरानी की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने आमजन से अपील की कि फ्लू जैसे लक्षण होने पर समय पर चिकित्सकीय सलाह लें और बिना चिकित्सकीय सलाह के एंटीबायोटिक, एंटीवायरल अथवा अन्य दवाओं का सेवन न करें। स्वाइन फ्लू, जिसे सामान्यतः इन्फ्लुएंजा– ।भ्1छ1कहा जाता है, एक श्वसन संबंधी वायरल संक्रमण है। इसके सामान्य लक्षणों में बुखार, खांसी, गले में खराश, नाक बहना या बंद होना, सिरदर्द, शरीर में दर्द, कमजोरी एवं थकान शामिल हो सकते हैं। अधिकांश मरीज उचित देखभाल एवं चिकित्सकीय सलाह से ठीक हो जाते हैं, हालांकि कुछ मामलों में संक्रमण गंभीर रूप ले सकता है। छोटे बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं तथा पहले से गंभीर बीमारी से ग्रसित या कमजोर प्रतिरक्षा वाले व्यक्तियों में विशेष सावधानी आवश्यक है। सांस लेने में कठिनाई या सांस फूलना, सीने में दर्द, अत्यधिक कमजोरी, लगातार बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति, अत्यधिक सुस्ती, भ्रम अथवा चेतना में बदलाव जैसे गंभीर लक्षण दिखाई देने पर तत्काल चिकित्सा सहायता प्राप्त करनी चाहिए। संक्रमण से बचाव के लिए खांसते या छींकते समय मुंह एवं नाक को रुमाल, टिश्यू अथवा कोहनी से ढकें, साबुन एवं पानी से नियमित रूप से हाथ धोएं और आवश्यकता होने पर हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग करें। बुखार, खांसी अथवा अन्य श्वसन संबंधी लक्षण होने पर भीड़भाड़ वाले स्थानों एवं निकट संपर्क से बचें तथा आवश्यकता के अनुसार मास्क का उपयोग करें। व्यक्तिगत वस्तुओं को साझा करने से बचें और बीमारी के दौरान पर्याप्त आराम एवं तरल पदार्थों का सेवन करें। 'डॉ. अनुज सिंह, विभागाध्यक्ष, कम्युनिटी मेडिसिन विभाग' ने बताया कि स्वाइन फ्लू के प्रभावी नियंत्रण के लिए चिकित्सा सेवाओं के साथ–साथ समुदाय में वैज्ञानिक एवं प्रमाणित स्वास्थ्य जानकारी पहुंचाना आवश्यक है। इसी उद्देश्य से कम्युनिटी मेडिसिन विभाग द्वारा व्यापक 'जन–जागरूकता अभियान' संचालित किया जा रहा है। अभियान के अंतर्गत आमजन को स्वाइन फ्लू के लक्षणों, संक्रमण से बचाव, व्यक्तिगत स्वच्छता, श्वसन शिष्टाचार, मास्क के उचित उपयोग एवं समय पर चिकित्सकीय परामर्श के संबंध में जागरूक किया जा रहा है। प्रमाणित एवं सरल स्वास्थ्य संदेशों को व्यापक स्तर तक पहुंचाने के लिए 'पोस्टर, बैनर, जन–जागरूकता गतिविधियों तथा डिजिटल एवं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म' का उपयोग किया जा रहा है। डॉ. अनुज सिंह ने कहा कि अभियान का मुख्य उद्देश्य 'वैज्ञानिक जानकारी को जन–जन तक पहुंचाना, अपुष्ट सूचनाओं से उत्पन्न अनावश्यक जन–चिंता को कम करना तथा संक्रमण की रोकथाम में समुदाय की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना है।' उन्होंने आमजन से अपील की कि सोशल मीडिया पर प्रसारित किसी भी अपुष्ट सूचना को सत्य मानकर आगे साझा न करें और स्वास्थ्य संबंधी जानकारी के लिए अधिकृत स्रोतों पर ही भरोसा करें। चिकित्सा–महाविद्यालय प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग एवं कम्युनिटी मेडिसिन विभाग द्वारा 'चिकित्सा व्यवस्था, निगरानी एवं जन–जागरूकता' के स्तर पर समन्वित प्रयास किए जा रहे हैं। इन प्रयासों का उद्देश्य समय पर बीमारी की पहचान, आवश्यक उपचार, संक्रमण की रोकथाम तथा जनसामान्य में व्याप्त अनावश्यक चिंता को कम करना है। 'जनसामान्य से पुनः अपील है कि स्वाइन फ्लू या किसी अन्य प्रकार के बुखार से डरें नहीं, सावधान रहें। सही जानकारी अपनाएं, अफवाहों को रोकें, व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान रखें, लक्षण होने पर समय पर चिकित्सकीय सलाह लें और संक्रमण की रोकथाम में स्वास्थ्य विभाग एवं चिकित्सा संस्थानों का सहयोग करें।

ब्राह्मण एकता परिषद ने विभिन्न मांगों को लेकर किया प्रदर्शन, सौंपा ज्ञापन

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर,। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में सोमवार को कलेक्ट्रेट परिसर में ब्राह्मण एकता परिषद के अध्यक्ष पंकज शुक्ला के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ताओं ने विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति और केंद्र सरकार को संबोधित ज्ञापन संबंधित अधिकारी को सौंपा। परिषद ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ओर से उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए जारी नए नियमों को वापस लेने की मांग की। परिषद का आरोप है कि इन नियमों में एकपक्षीय प्रावधान हैं और झूठी शिकायतों से प्रभावित होने वाले विद्यार्थियों व शोधार्थियों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। परिषद ने नियमों को पूरी तरह वापस लेने अथवा उन्हें वर्ग–निरपेक्ष बनाने की मांग की। कार्यकर्ताओं ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के कथित दुरुपयोग पर रोक लगाने की भी मांग की। परिषद ने कहा कि किसी शिकायत पर मुकदमा दर्ज करने या गिरफ्तारी से पहले निष्पक्ष प्रारंभिक जांच की व्यवस्था की जानी चाहिए, ताकि निर्दोष लोगों को अनावश्यक परेशानी से बचाया जा सके। ज्ञापन में आरक्षण व्यवस्था में श्क्रीमी लेयरश के प्रावधान को सख्ती से लागू करने की मांग भी उठाई गई। परिषद ने एसी और एसटी वर्गों में भी क्रीमी लेयर लागू करने तथा भविष्य में आरक्षण का आधार सामाजिक एवं आर्थिक आवश्यकता को बनाए जाने की मांग की। परिषद ने उच्च शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं की फीस, छात्रवृत्ति और छात्रावास जैसी सुविधाओं में समान शैक्षणिक अवसर सुनिश्चित करने तथा योग्यता को सम्मान देने की मांग की। कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार से इन मुद्दों पर न्यायसंगत समीक्षा कर आवश्यक नीतिगत सुधार करने का आग्रह किया।

कुलपति ने हास्टल के छात्राओं संग किया भोजन,मेस की थाली में परखी खाने की गुणवत्ता

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर,। यूपी के जौनपुर में वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. आर. के. सिंह ने सोमवार को विश्वविद्यालय परिसर स्थित महिला छात्रावासों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने मीराबाई छात्रावास में छात्राओं के साथ बैठकर भोजन किया और खुद भोजन की गुणवत्ता को परखा। कुलपति के छात्राओं के साथ भोजन करने से छात्राओं में भी उत्साह देखने को मिला। भोजन के दौरान कुलपति ने छात्राओं से छात्रावास में मिलने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। उन्होंने उनके पठन–पाठन, अध्ययन के माहौल तथा छात्रावास में आने वाली समस्याओं के बारे में भी पूछा। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए बेहतर वातावरण उपलब्ध कराना विश्वविद्यालय की प्राथमिकता है। कुलपति ने छात्रावास की विभिन्न व्यवस्थाओं का निरीक्षण करते हुए अधिकारियों एवं वार्डन को निर्देश दिया कि छात्राओं को उपलब्ध कराई जाने वाली सभी सुविधाएं उच्च गुणवत्ता की होनी चाहिए। उन्होंने भोजन की गुणवत्ता के साथ–साथ साफ–सफाई, पेयजल और अन्य मूलभूत सुविधाओं पर विशेष ध्यान देने को कहा। उन्होंने छात्रावास में आने वाले अभिभावकों के लिए निर्धारित कक्ष में एसी लगवाने के भी निर्देश दिए, ताकि वहां आने वाले अभिभावकों को बेहतर सुविधा मिल सके। कुलपति प्रो. आर.के. सिंह ने कहा कि छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण के साथ सुविधाजनक, स्वच्छ एवं सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना विश्वविद्यालय की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि छात्राओं की सुविधाओं और उनकी आवश्यकताओं का लगातार ध्यान रखा जाना चाहिए। इस अवसर पर कुलपति ने द्रौपदी, मीराबाई एवं रानी लक्ष्मीबाई महिला छात्रावास की वार्डन डॉ. कृष्णा सिंह, डॉ. निमिषा यादव एवं डॉ. जया शुक्ला से छात्रावासों की व्यवस्थाओं के बारे में विस्तार से जानकारी ली। इस अवसर पर चीफ वार्डन प्रो. अविनाश पाथर्डीकर, प्रो. गिरधर मिश्र, डॉ. प्रियंका सिंह, डॉ. वनिता सिंह एवं डॉ. श्वेता पांडेय उपस्थित रहीं।

बूथों पर गूंजी 'मन की बात', कार्यकर्ताओं ने सुना प्रधानमंत्री का संदेश

अयोध्या। भारतीय जनता पार्टी अयोध्या महानगर के सभी 419 बूथों पर रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' का सामूहिक श्रवण किया गया। बूथ स्तर पर आयोजित कार्यक्रमों में जनप्रतिनिधियों, पार्टी पदाधिकारियों, बूथ समितियों के सदस्यों और स्थानीय नागरिकों ने प्रधानमंत्री का संदेश सुना। कार्यक्रम के बाद कार्यकर्ताओं ने इसमें उठाए गए विषयों और सामाजिक सरोकारों पर चर्चा की। जिला पंचायत प्रशासक रोली सिंह ने कौशलपुरी में मन की बात सुनी। कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 'मन की बात' कार्यक्रम देशवासियों को समाज और राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का बोध कराता है। विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री कार्यक्रम के माध्यम से देशभर में किए जा रहे प्रेरणादायी कार्यों और प्रयासों को सामने लाते हैं, जिससे आम नागरिकों को राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाने की प्रेरणा मिलती है। मिल्कीपुर मंडल के उधौइ में भाजपा जिलाध्यक्ष राधेश्याम त्यागी और महापौर महंत गिरीश पति त्रिपाठी ने कार्यकर्ताओं के साथ कार्यक्रम सुना। महापौर ने कहा कि 'मन की बात' को सामाजिक चेतना और जनभागीदारी को बढ़ाने वाला प्रभावी माध्यम बताया। जिलाध्यक्ष ने कहा कि कहा कि 'मन की बात' जनभागीदारी और सकारात्मक सोच को मजबूत करने का प्रभावी माध्यम बन चुका है। भाजपा महानगर कार्यालय में महानगर अध्यक्ष कमलेश श्रीवास्तव ने पार्टी पदाधिकारियों के साथ कार्यक्रम का श्रवण किया। उन्होंने कहा कि बूथ संगठन की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है और प्रधानमंत्री के संदेशों को कार्यकर्ता समाज के बीच पहुंचाने का काम करेंगे। विद्याकुंड वार्ड में पूर्व महापौर ऋषिकेश उपाध्याय और महानगर महामंत्री परमानंद मिश्र ने कार्यकर्ताओं के साथ 'मन की बात' सुनी। वहीं मीडिया प्रभारी अमित कुमार मिश्र ने अंजनीपुरम शक्ति केंद्र, मंडल अध्यक्ष मुकेश तिवारी ने हनुमानगढ़ी शक्ति केंद्र, हेमंत जायसवाल ने दिल्ली दरवाजा तथा रवि सोनकर ने बेगमगंज गढ़ैया में स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ कार्यक्रम में सहभागिता की। इसके अलावा महानगर के विभिन्न बूथों और शक्ति केंद्रों पर शैलेंद्र कोरी, अरविंद सिंह, हरभजन गौड़, शिवम शुक्ला, रीना द्विवेदी, गरिमा मौर्या, प्रवीण दुबे, प्रदीप यादव और जेपी श्रीवास्तव समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता ने कार्यक्रम को सामूहिक रूप से सुना।

'अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद कानपुर प्रांत के अध्यक्ष व सरंक्षक लेफ्टिनेंट कर्नल बृजपाल सिंह राठौड़ पंच तत्व में हुए विलीन'

1. विनम्रता पूर्वक अवगत कराया था कि हमारे बीच परिषद के लगभग 10 वर्ष से प्रांतीय अध्यक्ष व दिनांक 13 अगस्त 2026 से सरंक्षक का दायित्व पर रहते हुए लेफ्टिनेंट कर्नल बृजपाल सिंह राठौड़ नहीं रहे ! उनके र्स्वगवास के सूचना से कानपुर प्रांत में आने वाले सभी जनपदों में शोक की लहर से सभी के दिलों को झकझोर दिया ! राठौड़ साहब का अंतिम संस्कार पर दिनांक 30 अगस्त 2026 – समय लगभग 1330 बजे स्टेशन मुख्यालय, कानपुर कैंट से एक अधिकारी के साथ कनिष्ट अधिकारी और जवानों की टुकड़ी ने राष्ट्रीय ध्वज, रीति और पुष्पांजलि के साथ सलामी दी ! इस प्रक्रिया में कानपुर प्रांत के अध्यक्ष कमांडर नवीन कटियार, फर्रूखाघाबाद से फर्रूखघबाद के इकाई के अध्यक्ष कैप्टन आर के सिंह जादौन, सरंक्षक – कैप्टन उदय राज सिंह (प्रथम अध्यक्ष अब सरंक्षक) नायब सूबेदार सी. पी. सिंह परिहार, सरंक्षक के अन्य 02 सक्रिय कार्यकर्ता, लखनऊ से अवध प्रांत के अध्यक्ष, ले. कर्नल बीरेंद्र सिंह तोमर, कन्नौज से सूबेदार प्रमोद सिंह चौहान और 04 सदस्यगण, फतेहपुर इकाई से हवलदार जितेंद्र सिंह गौतम आत्मज कैप्टन पितांबर

सिंह, अध्यक्ष, व हवलदार राजेश सिंह परिहार, कानपुर प्रांतध्इकाई से 10 की संख्या मे साहब के पैतृक गांव लालूपुर, घाटमपुर के पास गए और उधर से ही साथ में सीधे अंतिम संस्कार स्थल डयोढ़ी घाट, गंगा नदी पहुंचे ! कानपुर प्रांतध्इकाई शहर से ले. कर्नल आर पी यादव, विंग कमांडर आर यस भदौरिया, उपाध्यक्ष प्रांत, महासचिव प्रांत, सूबेदार मेजर(भ्वदल रुज) चरन सिंह यादव, कैप्टन अजय सिंह चौहान, सूबेदार मेजर आर सी यादव, सूबेदार मेजर आर एन यादव, सूबेदार राम प्रसाद पाल, सूबेदार मेजर नरेंद्र कुमार मिश्रा (परिषद प्रदेश सचिव, उत्तर प्रदेश), सूबेदार मेजर राकेश सिंह चंदेल, सूबेदार मेजर विपिन कुमार मिश्रा, ए.सी. दिलीप कुमार दीक्षित, सूबेदार एस एन सिंह व इकाई के अध्यक्ष के साथ 45 पूर्व सैनिक साथी एवं शहर व पैतृक गांव से सैंकड़ो की संख्या में गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति ने अतेष्टि स्थल पर नम आंखों से दिवंगत साहब को भावभीनि श्रदांजलि अर्पित की ! दिवंगत साहब के परिजन व पुत्र, देवेंद्र सिंह राठौड़ संपर्क सूत्र 9956110022 से मिलकर कर्नल राठौर साहब के साथ गुजारे दशकों वर्ष, फरूखाबाद इकाई से आए पदाधिकारियों में कैप्टन उदय राज सिंह व नायब सूबेदार सी पी सिंह परिहार साहब वर्ष 1994 से अभी तक का साथ रहा ।

एक राष्ट्र, एक समान कानून और समान अधिकार की मांग, सवर्ण आर्मी ने किया माग सौंपा ज्ञापन

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर,। यूपी के जौनपुर में कलेक्ट्रेट परिसर में सोमवार को सवर्ण आर्मी के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट माहिपाल सिंह यादव को सौंपा। प्रदेश उपाध्यक्ष प्रवीण तिवारी के नेतृत्व में पहुंचे कार्यकर्ताओं ने देश में 'एक राष्ट्र, एक समान कानून' लागू करने तथा सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करने की मांग की। इस मौक पर प्रवीण तिवारी ने कहा कि संविधान प्रत्येक नागरिक को समानता और मौलिक अधिकार प्रदान करता है। इसलिए कानून के शासन, समानता और न्याय के संवैधानिक सिद्धांतों को और मजबूत किए जाने की आवश्यकता है। ज्ञापन में आरक्षण व्यवस्था की समीक्षा की मांग करते हुए आर्थिक स्थिति तथा वास्तविक सामाजिक–शैक्षिक पिछड़ेपन जैसे पारदर्शी मानकों को आधार बनाने का सुझाव दिया गया। साथ ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की ओर से वर्ष 2026 में बनाए गए नए नियमों की पुनः समीक्षा करने और जनहित के अनुरूप न पाए जाने वाले प्रावधानों को वापस लेने पर विचार करने की अपील की गई। कार्यकर्ताओं ने एससीध्एसटी एक्ट के तहत दर्ज मामलों से संबंधित अधिकृत और सत्यापित आंकड़े सार्वजनिक करने की भी मांग की। उन्होंने कानून के दुरुपयोग की संभावना रोकने के लिए उचित सुरक्षा प्रावधान और निष्पक्ष जांच व्यवस्था सुनिश्चित करने पर जोर दिया। सवर्ण आर्मी ने सभी जाति और धर्म के नागरिकों को संविधान के अनुरूप समान अधिकार, सम्मान और न्याय दिलाने की मांग की। इसके अलावा सवर्ण समाज की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक समस्याओं के अध्ययन एवं समाधान के लिए वैधानिक सवर्ण आयोग के गठन पर विचार करने की मांग भी ज्ञापन में की गई।

देश की सबसे बड़ी रामलीला में पहली बार तीन वर्ष के बच्चे करेंगे अभिनय

अयोध्या। अयोध्या से चर्चित फिल्मी कलाकारों की रामलीला को देश की सबसे बड़ी रामलीला माना जाता है। इस वर्ष पहली बार दिल्ली में अपना आठवां संस्करण प्रस्तुत करेगी। इस भव्य आयोजन में तीन वर्ष के छोटे बच्चों से लेकर सोलह वर्ष तक के बाल कलाकार सुबह के सत्र में अभिनय करेंगे, जबकि शाम को साठ से अधिक फिल्मी सितारे मंच पर नजर आएंगे। नवां संस्करण दो माह बाद जनवरी में अयोध्या में आयोजित होगा। यह रामलीला कोरोना काल में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल से शुरू हुई थी और अब यह विश्व स्तर पर रामभक्ति का संदेश पहुंचा रही है। दिल्ली में आयोजन 10 से 20 अक्टूबर 2026 तक नई दिल्ली स्थित रफी मार्ग पर कांस्टीट्यूशन क्लब के मावलंकर हॉल में होगा। यहां सुबह 10 बजे से 12 बजे तक तीन से सोलह वर्ष के बच्चे अयोध्या की रामलीला में भाग लेंगे। शाम 7 बजे से 10 बजे तक फिल्मी कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। आयोजन स्थल पर शाम 4 बजे से रात 11 बजे तक मेले का भी आयोजन होगा। हॉल की बैठने की क्षमता करीब 600 लोगों की है। 120 फीट लंबी एलईडी टीवी स्क्रीन लगाई जाएगी, ताकि दर्शकों को भव्य दृश्य स्पष्ट रूप से दिखाई दें। माना जा रहा है कि इतनी कम उम्र के बच्चों वाली रामलीला पहली बार हो रही है। इसमें भगवान श्रीराम के बचपन के स्वरूपों को भी विशेष रूप से दिखाया जाएगा। यह आयोजन न केवल कलाकारों के अभिनय से यादगार बनेगा, बल्कि तकनीकी व्यवस्थाओं जैसे विशाल एलईडी स्क्रीन और बहुभाषी प्रसारण से भी नए आयाम स्थापित करेगा। संस्थापक सुभाष मलिक (बॉबी)और शुभम मलिक की अगुवाई में टीम लगातार तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सहयोग से शुरू हुई यह रामलीला अब राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना चुकी है। दिल्लीवासियों और देश–विदेश के रामभक्तों के लिए यह सुनहरा अवसर है कि वे मावलंकर हॉल में पहुंचकर या टीवी पर बैठकर इस अद्वितीय रामलीला का आनंद लें। अक्टूबर में दिल्ली और जनवरी में अयोध्या दोनों स्थानों पर रामकथा का मंच सजेगा और करोड़ों दिलों में भक्ति का संचार होगा। प्रभु श्रीराम की भूमिका में गोरखपुर सांसद और भोजपुरी–बॉलीवुड स्टार रवि किशन नजर आएंगे। 19 अक्टूबर को वे पहली बार राम का किरदार निभाएंगे। इससे पहले वे केवट, भगवान परशुराम और भरत की भूमिकाएं अदा कर चुके हैं। लंकापति रावण की भूमिका में अरुण बख्शी होंगे। बिंदु दारा सिंह भगवान शिव के रूप में, पुनीत इस्सर भगवान परशुराम के रूप में, रजा मुराद अहिरावण के रूप में और अवतार गिल मेघनाद के रूप में मंच पर आएंगे। कुल मिलाकर साठ से अधिक फिल्मी सितारे इस रामलीला में अभिनय करेंगे। रिहर्सल दिल्ली और मुंबई के कलाकार कर रहे हैं। अयोध्या में नवां संस्करण 15 जनवरी 2027 से 25 जनवरी 2027 तक होगा। अब तक अयोध्या में सात संस्करण सफलतापूर्वक आयोजित हो चुके हैं। कोरोना काल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस रामलीला को अनुमति दी थी, जो आज संसार की सबसे बड़ी रामलीला बन चुकी है। सुभाष मलिक बताते हैं कि पिछले वर्ष इस प्रस्तुति को 62 करोड़ से अधिक रामभक्तों ने अपने घर बैठे देखा। इस वर्ष भी 80 से अधिक सैटेलाइट चौनलों पर 40 भाषाओं में इसका प्रसारण होगा। साठ से अधिक देशों तक रामभक्ति का संदेश पहुंचेगा। देश–विदेश के दर्शक इस भव्य प्रस्तुति का आनंद ले सकेंगे। अयोध्या की रामलीला न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन है, बल्कि यह बच्चों को रामकथा से जोड़ने का भी माध्यम बन रही है। तीन वर्ष के छोटे बच्चे मंच पर आकर भगवान के बाल स्वरूप को जीवंत करेंगे, जो इस आयोजन को और भी विशेष बनाता है। दिल्ली में पहली बार होने वाला यह संस्करण राजधानी के लोगों को अयोध्या की भव्यता का अनुभव कराएगा। मेले के साथ जुड़ी गतिविधियों से पूरा माहौल राममय हो जाएगा।

उमानाथ सिंह मेडिकल कॉलेज में ब्लड सेंटर को केंद्रीय स्तर से मंजूरी - डॉ आर बी कमल प्राचार्य

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर,। उत्तर प्रदेश के जौनपुर स्थित उमानाथ सिंह स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, सिद्दीकपुर में ब्लड सेंटर के संचालन को केंद्रीय स्तर से स्वीकृति मिल गई है। इससे मेडिकल कॉलेज में रक्त के संग्रह, प्रसंस्करण और सुरक्षित भंडारण के साथ ही रक्त के विभिन्न अवयवों की उपलब्धता का रास्ता साफ हो गया है। ब्लड सेंटर शुरू होने के बाद मेडिकल कॉलेज में भर्ती मरीजों को जरूरत के समय रक्त उपलब्ध कराने में काफी सहूलियत होगी। जनपद में जिला अस्पताल में पहले से रक्त की सुविधा उपलब्ध है, लेकिन कई बार मांग के अनुरूप रक्त अथवा आवश्यक रक्त अवयव उपलब्ध नहीं होने से मरीजों और उनके तीमारदारों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में उन्हें निजी केंद्रों से रक्त की व्यवस्था करनी पड़ती थी या वाराणसी सहित अन्य शहरों का रुख करना पड़ता था। मेडिकल कॉलेज में ब्लड सेंटर की सुविधा शुरू होने से गंभीर मरीजों, दुर्घटना में घायलों, प्रसूताओं और ऑपरेशन वाले मरीजों को तत्काल रक्त उपलब्ध कराने की व्यवस्था मजबूत होगी। जरूरत के अनुसार प्लेटलेट्स और प्लाज्मा जैसे रक्त अवयव भी उपलब्ध कराने की दिशा में सुविधा विकसित की जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य सेवाओं के अधीन केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) के ब्लड सेंटर प्रभाग की ओर से मेडिकल कॉलेज को संचालन की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके तहत निर्धारित मानकों के अनुसार रक्त एवं उसके अवयवों का संग्रह, प्रसंस्करण और सुरक्षित भंडारण किया जाएगा। मेडिकल कॉलेज प्रबंधन के अनुसार ब्लड सेंटर के लिए आवश्यक मशीनें भी तैयार हैं।इस संबंध में सोमवार को जानकारी लेने पर मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. आरबी कमल ने बताया कि मेडिकल कॉलेज को ब्लड सेंटर के लिए मान्यता प्राप्त हो चुकी है और सभी आवश्यक मशीनें तैयार हैं। अब यहां मरीजों को ब्लड सेंटर के माध्यम से रक्त उपलब्ध कराया जा सकेगा। इससे ऑपरेशन कराने वाले और अन्य भर्ती मरीजों को जरूरत के समय मेडिकल कॉलेज में ही रक्त मिल सकेगा और उन्हें रक्त की व्यवस्था के लिए इधर–उधर भटकना नहीं पड़ेगा। मेडिकल कॉलेज में ब्लड सेंटर की सुविधा उपलब्ध होने से जिला अस्पताल पर रक्त की मांग का दबाव भी कम होने की उम्मीद है। साथ ही मरीजों को निजी संस्थानों में अधिक खर्च करने अथवा दूसरे शहरों में जाकर रक्त की व्यवस्था करने की परेशानी से राहत मिलेगी।

अयोध्या के पांच शिक्षकों को मिलेगा 'मुलायम सिंह यादव शिक्षक सम्मान'

अयोध्या। समाजवादी शिक्षक सभा की ओर से शिक्षक दिवस के अवसर पर तीन सितंबर को 'मुलायम सिंह यादव शिक्षक सम्मान 2025–26' समारोह का आयोजन किया जाएगा। गुलाबबाड़ी स्थित समाजवादी पार्टी लोहिया भवन में

दोपहर एक बजे होने वाले समारोह में जनपद के पांच उत्कृष्ट शिक्षक–शिक्षिकाओं को सम्मानित किया जाएगा। यह जानकारी रविवार को संगठन के जिलाध्यक्ष दान बहादुर सिंह ने प्रेस वार्ता में दी। उन्होंने बताया कि सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि आजमगढ़ के सांसद धर्मेंद्र यादव होंगे। विशिष्ट अतिथि शिक्षक सभा के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. एसपी सिंह पटेल, प्रमुख महासचिव डॉ. कमलेश यादव और मंडल प्रभारी डॉ. जितेंद्र मिश्रा होंगे। सम्मान की शुरुआत वर्ष 2012 में हुई थी और तब से यह आयोजन निरंतर किया जा रहा है। इस वर्ष चार सितंबर को श्रीकृष्ण जन्माष्टमी होने के कारण समारोह एक दिन पूर्व आयोजित किया जा रहा है। इसबार सम्मान के लिए चयनित शिक्षकों में डॉ. मीनाक्षी यादव, कार्यवाहक प्रधानाध्यापिका प्राथमिक विद्यालय उसरू अमोना, मसौधा, सुल्ताना बानो, सहायक अध्यापिका राजकीय हाईस्कूल बहरास, रुदौली, राकेश कुमार वर्मा, सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय चन्दीपुर नघरा, हैरिंग्टीनगंज, बृजेश कुमार, कार्यवाहक प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय कलापुर, मवई तथा डॉ. जन्मेजय तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, का.सु. साकेत महाविद्यालय शामिल हैं। सम्मान समारोह के बाद शैक्षिक उन्नयन गोष्ठी भी आयोजित होगी। इसमें सांसद, पूर्व मंत्री, विधायक, जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष सहित अन्य वक्ता शिक्षकों को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम में पार्टी नेताओं, कार्यकर्ताओं और जनपद के शिक्षकों को भी आमंत्रित किया गया है। प्रेसवार्ता के दौरान शिक्षक सभा महासचिव डॉ. घनश्याम यादव, प्रवक्ता राकेश यादव, चयन समिति के सदस्य विमल सिंह यादव, प्रभाकर सिंह, तहसीलदार सिंह, अमरनाथ सिंह, प्रदीप कुमार तिवारी, रणधीर सिंह, अवनीश प्रताप सिंह, मृत्युंजय सिंह, मौजूद रहे।

रेलवे स्टेशन मार्ग पर बनेगा फूड प्वाइंट, फव्वारे का होगा कायाकल्प

अयोध्या। रेलवे स्टेशन जाने वाले मार्ग पर भाजपा कार्यालय के निकट फूड प्वाइंट विकसित किया जाएगा। वहीं गुरु गोविंद सिंह चौक स्थित फव्वारे का कायाकल्प कराया जाएगा। रविवार को नगर भ्रमण एवं सफाई अभियान के दौरान महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी ने अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान उनके साथ नगर आयुक्त जयेंद्र कुमार भी थे। महापौर ने अशफाक उल्ला खां वार्ड में जेल के पीछे स्थित पार्किंग स्थल पर सफाई अभियान चलाकर स्वच्छता व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने में नगर निगम के साथ नागरिकों की सहभागिता भी बेहद जरूरी है। नगर निगम की ओर से जनसहयोग से स्वच्छता को लेकर विशेष जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत लोगों को सार्वजनिक स्थलों पर कूड़ा न फेंकने, गीला–सूखा कचरा अलग रखने और अपने आसपास के क्षेत्र को साफ रखने के लिए प्रेरित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्वच्छता केवल अभियान तक सीमित न रहकर नागरिकों की दैनिक आदत का हिस्सा बननी चाहिए। सार्वजनिक स्थानों की स्वच्छता बनाए रखने में दुकानदारों और स्थानीय नागरिकों की जिम्मेदारी भी अहम है। सफाई अभियान के बाद महापौर और नगर निगम की टीम ने पैदल निरीक्षण किया। स्टेशन रोड की ओर बढ़ने पर तालाब के सामने पीपल के वृक्ष के पास चबूतरा बनवाने का निर्देश दिया गया। यहां स्थित मार्केट हाउस के आसपास भी व्यवस्थाओं को बेहतर करने के निर्देश दिए गए। तालाब एवं हरित क्षेत्र को साफ–सुथरा कर जनोपयोगी बनाने का सुझाव पार्षद अखिलेश पांडे ने दिया। इस पर नगर आयुक्त जयेंद्र कुमार ने संबंधित विभागों से समन्वय कर आवश्यक कार्रवाई का भरोसा दिलाया। भाजपा कार्यालय के निकट प्रकाश व्यवस्था बेहतर करने के लिए लाइट लगवाने का निर्देश भी महापौर ने दिया। निरीक्षण के दौरान सड़क किनारे निर्मित नाली की स्थिति का जायजा लेकर उसकी खामियां दूर करने के निर्देश दिए गए। नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी मुकेश पांडे ने बताया कि गुरु गोविंद सिंह चौक पहुंचने पर फव्वारे की बदहाल स्थिति देखकर महापौर ने नाराजगी जताई। उन्होंने फव्वारे के कायाकल्प के लिए कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। इस दौरान स्थानीय व्यापारियों और फुटपाथ दुकानदारों ने दुकान लगाने के लिए स्थान उपलब्ध कराने की मांग रखी। क्षेत्रीय पार्षद दीप कुमार ने भी मांग का समर्थन किया। महापौर ने व्यापारियों को व्यवस्थित स्थान उपलब्ध कराने के लिए फूड प्वाइंट विकसित करने का भरोसा दिलाया। इस दौरान अपर नगर आयुक्त भारत भार्गव, जोनल अधिकारी सुभाष त्रिपाठी समेत नगर निगम के अधिकारी–कर्मचारी मौजूद रहे।

नहीं रहा आरोग्य मेले का माहौल, रोज की तरह आते रहे मरीज

सोहावल–अयोध्या। रविवार को आयोजित होने वाले जन आरोग्य मेले में मेले का माहौल ही नहीं दिखाई पड़ा। रोज की तरह एक एक करके मरीज आते जाते रहे। मेले का हिस्सा रहे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मुबारकगंज में मेले जैसा कुछ नहीं रहा। यहां तैनात किए गए इकलौते चिकित्सक

इकबाल और फार्मासिस्ट देव सरन मौर्य ने साथ मिलकर मरीजों को देखा। केंद्र पर कुल 68 मरीज पंजीकृत हुए । इनमें महिलाओं की संख्या ज्यादा रही लेकिन महिला चिकित्सक की नियुक्ति नहीं रही। होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी चिकित्सकों की सोहावल में चिकित्सालय होने के बावजूद इनके चिकित्सकों की नियुक्ति मेले में नहीं की गयी। मरीजों के कम आने से प्रतीक्षा हाल लगभग खाली रहा। इमरजेंसी कक्ष का ताला खुलने की नौबत ही नहीं आयी। पूछे जाने पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी आकांक्षा वर्मा ने बताया कि ज्यादातर चिकित्सकों की इमरजेंसी ड्यूटी पुलिस लाइन में लग जाने से आयुष डाक्टरों ने आरोग्य के मेले में अपना योगदान दिया। केंद्र की पैथालाजी सक्रिय रही। शासन से उपलब्ध सभी सेवाएं मरीजों को प्रदान की गई।

कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष की सभा के बाद सभा स्थल का शुद्धिकरण किए जाने से कांग्रेसी नाराज

रूदौली–अयोध्या। उत्तराखंड के हल्द्वानी में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष व राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे की सभा के बाद रामलीला मैदान में कथित तौर पर किए गए शुद्धिकरण को लेकर कांग्रेस नेता दयानन्द शुक्ला के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बाबा बाजार थाना पहुंच कर थाना प्रभारी शैलेन्द्र कुमार आजाद को ज्ञापन देकर भाजपा नेताओं पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। थाना प्रभारी को दी गई तहरीर में दयानन्द शुक्ला ने बताया कि भाजपा के कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार से रैली स्थल को शुद्धिकरण के नाम पर धोया पोछा पूजा पाठ किया वह घोर निंदनीय है। छुआ छूत को बढ़ावा देने वाला दूषित मानसिकता और दलित का अपमान करने वाला है। उन्होंने कहा कि एक बुजुर्ग दलित नेता का अपमान ही नहीं बल्कि पूरे दालि समाज का अपमान है। भाजपा नेताओं की इस प्रकार की गई हरकत से यह साबित हो गया है कि भाजपा दलित विरोधी है। भाजपा नेताओं ने इस प्रकार की हरकत करके देश के लाखों दलितों का अपमान किया है। कांग्रेस नेता दयानंद शुक्ला ने कहा यह मामला केवल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नहीं है।बल्कि देश के हर दलित व्यक्ति से सम्बंधित है।संविधान छुआ छूत को गैर कानूनी बनाता है।और यदि किसी व्यक्ति या समूह के साथ उसकी जाति के आधार पर ऐसा व्यवहार किया जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए।उन्होंने भाजपा और आर एस एस की विचार धारा पर हमला करते हुए कहा कि ऐसी घटनाएं उस सामाजिक सोच को दिखाती है। जिसमें दलितों को बराबरी और सम्मान देने के बजाय उन्हें अलग समझा जाता है। इस अवसर पर कांग्रेस के जिला महासचिव रणजीत सिंह, संजय तिवारी, ब्लॉक अध्यक्ष परमानंद शुक्ला, रामकृष्ण शुक्ला, राम आशीष तिवारी, गौरव शुक्ला, मोबीन अहमद, चंद्र कुमार कौशल, सुशील तिवारी, पवन शुक्ला, हरिकेश मौर्य आदि लोग उपस्थित थे।

नगर निगम के कूड़ा वाहन से टकराया बाइक सवार युवक, मौत

अयोध्या। कोतवाली नगर क्षेत्र के अंगूरीबाग में रविवार सुबह बारिश के बाद सड़क पर हुई फिसलन एक युवक की जिंदगी पर भारी पड़ गई। गाय को बचाने के प्रयास में बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े नगर निगम के कूड़ा वाहन से जा टकराई। हादसे में बाइक सवार 17 वर्षीय युवक की मौत हो गई। हादसे के समय युवक ने हेलमेट नहीं पहना था। मृतक की पहचान इमामबाड़ा राठहवेली निवासी मो. सोएब सिद्दीकी के पुत्र ऐहेतेसाम सिद्दीकी उर्फ लकी के रूप में हुई है। लकी जेईई की तैयारी कर रहा था और चार भाइयों में तीसरे नंबर पर था। परिजनों के मुताबिक, लकी के पिता मो. सोएब सिद्दीकी बीएसए कार्यालय में लिपिक पद पर तैनात हैं और इन दिनों अस्पताल में भर्ती हैं। रविवार सुबह लकी बाइक से अस्पताल गया था और पिता को नाश्ता–पानी देने के बाद घर लौट रहा था। अंगूरीबाग प्राथमिक विद्यालय के सामने अचानक गाय के आ जाने पर उसे बचाने के लिए उसने ब्रेक लगाया। बारिश के कारण सड़क पर फिसलन होने से बाइक अनियंत्रित हो गई और वह सड़क किनारे खड़े नगर निगम के कूड़ा वाहन से जा भिड़ा। टक्कर इतनी जोरदार थी कि उसका सिर वाहन से टकरा गया। हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस और एंबुलेंस को सूचना दी। प्रत्यक्षदर्शी मुकेश सोनकर ने बताया कि सुबह करीब साढ़े सात बजे बारिश हुई थी। नगर निगम का वाहन सड़क किनारे खड़ा था। बाइक अनियंत्रित होने के बाद युवक ने नगर निगम के खड़े वाहन को टक्कर मार दी। एंबुलेंस से उसे अस्पताल भेजा गया। फार्ब्स इंटर कॉलेज के शिक्षक मो. आसिफ ने बताया कि लकी काफी मिलनसार स्वभाव का था और पढ़ाई में आगे बढ़ने के लिए जेईई की तैयारी कर रहा था। हादसे की खबर से परिवार और परिचितों में शोक का माहौल है। प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर मनोज शर्मा ने बताया कि हादसे में मृत युवक की पहचान ऐहेतेसाम सिद्दीकी उर्फ लकी के रूप में हुई है।

रेलवे ट्रैक पर मिला युवक का शव

सोहावल–अयोध्या।रौनाही थाना क्षेत्र में देवराकोट रेलवे स्टेशन के पास शनिवार को रेलवे ट्रैक पर लगभग 30 वर्षीय युवक का शव मिला। पुलिस की जाँच पड़ताल में मृतक की फूल कुमार पुत्र हृदय राम निवासी शिव दयाल का पुरवा ग्राम पंचायत हाजीपुर बरसेंडी के रूप में पहचान हुई है।सूचना पर पहुंची रौनाही पुलिस ने शव को कब्जे मे लेकर पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है । मामले में अग्रिम विधिक कार्रवाई जारी है।

ढोल नगाड़ों के साथ घर-घर दिया सुकन्या का दस्तक

अयोध्या। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओष् के अंतर्गत मण्डल डाकघर के अधिकारी एवं कर्मचारियों ने मण्डल के 714 डाकघरों के गांवों में दरवाजे दरवाजे पर बचत व सुकन्या समृद्धि योजना के लिए नुक्कड़ सभा, ढोल नगाड़ों के साथ दस्तक देकर हजारों खाता खोले । अपनी बेटियों के उज्ज्वल भविष्य को लेकर ग्रामीणों ने सुकन्या समृद्धि योजना की सराहना भी किया, इस बीच अयोध्या मण्डल के अधीक्षक डाकघर मनोज कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि आज मण्डल के सभी कर्मचारियों ने डाकघर के गांवों में दरवाजे दरवाजे पर सम्पर्क कर उन्हें जागरूक करके बचत तथा सुकन्या समृद्धि के हजारों खाता खोले । साथ ही उन्होंने कहा कि सुकन्या समृद्धि में थोड़ा थोड़ा धन जमा करके बेटी को दें उज्ज्वल भविष्य की सौगात ।

बेटियों के समृद्ध होने से समाज की दिशा बदलेगी । श्री मनोज ने यह भी कहा कि भारत सरकार द्वारा नारी सशक्तिकरण की दिशा में तमाम महत्वपूर्ण योजनाएँ चलायी जा रही हैं। इसी क्रम में डाकघरों में सुकन्या समृद्धि योजना में धन जमा करने से माँ–बाप अपनी बेटी के भविष्य को संवारने में अहम भूमिका निभायेंगे। इससे बेटियों को आर्थिक व सामाजिक रूप से भविष्य में मजबूत किया जा सकता है। कन्या भ्रूण हत्या रोकने, महिला सशक्तिकरण, उच्च शिक्षा में सुकन्या समृद्धि योजना राष्ट्र निर्माण में सहायक होगी। और बताया कि मात्र 250 रूपये में सुकन्या खाता खोला जा सकता है और इसमें अधिकतम डेढ़ लाख रूपये जमा किये जा सकते हैं। इस योजना में खाता खोलने से मात्र 15 वर्ष तक धन जमा कराना होगा। बेटी की उम्र 18 वर्ष होने पर जमा राशि का 50 प्रतिशत व सम्पूर्ण राशि 21 वर्ष पूरा होने पर निकाली जा सकती है। वर्तमान में सर्वाधिक ब्याज दर 8.2 प्रतिशत है और जमा धनराशि में आयकर छूट का भी प्रावधान है।

देश पर मर मिटने वालों के त्याग व बलिदान को देश भुला नहीं सकता- टिल्लू

अयोध्या। कचेहरी स्थित स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी भवन में रविवार को अपरान्ह 12 बजे जनपद के प्रख्यात क्रान्तिकारी एवं स्वतन्त्रता

आन्दोलन में जनपद फैजाबाद के क्रान्तिकारियों में प्रमुख क्रान्तिकारी डॉ. सुरेन्द्र नाथ अग्रहरि को आज उनके पुण्यतिथि पर श्रद्धाजंलि सभा आयोजित करके, उन्हें भावभीनी श्रद्धाजंलि अर्पित की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए कोऑपरोटिव बैंक के सभापति धर्मेन्द्र प्रताप सिंह टिल्लू ने कहा कि देश के अमर बलिदानियों तथा देश पर मर मिटने वालों के त्याग व बलिदान को देश भुला नहीं सकता। आजादी के सिपाहियों का सम्मान करना हम सब का नैतिक कर्तव्य है। अग्रहरि समाज के प्रदेश कोषाध्यक्ष देवेन्द्र गुप्ता अग्रहरि ने कहा कि आजादी के इन दीवानों के दिखाये मार्ग पर चलकर ही हम उन्हें सच्ची श्रृद्धाजलि दे सकते हैं। सेनानी परिषद के सचिव मनोज मेहरोत्रा ने कहा कि देश पर मर मिटने वालों के ऋण को कभी कोई सरकारें चुका नहीं सकती। आज सेनानी परिवारो की उपेक्षा से ऐसा प्रतीत होता है कि सरकारे इस विषय पर गंभीर नहीं है। उन्होने कहा है कि डॉ. सुरेन्द्र नाथ अग्रहरि फैजाबाद जनपद के सशस्त्र क्रान्ति के अग्रणी नेता थे। डॉ. सुरेन्द्र नाथ अग्रहरि ने आजादी की लड़ाई के दौरान अग्रेजो की जो प्रताड़ना सही थी। वो कष्ट सहन करनें का जज्बा आजादी के इन दिवानों के ही बस का था। वहीं भाजपा पार्षद हरिश्चन्द्र अग्रहरी ने कहा कि बाबू जी की यादे आज भी हम सेनानी वंशजों के दिलों दिमाग में एकदम ताजा हैं। याद करते ही आंखे भर आती हैं। वहीं सेनानी बंशज दिव्य मोहन अग्रहरी ने कहा कि स्वतन्त्रता की लड़ाई में फैजाबाद के सेनानियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उक्त अवसर पर श्रद्धांजलि सभा का संचालन करते हुए वरिष्ठ भाजपा नेता केशव बिगुलर ने कहा कि आज देश में इन आजादी के योद्धाओं के जीवन गाथा से हमें भावी पीढ़ी को उनसे अवगत कराने की आवश्यकता है जिसके लिये इनके जीवन गाथाओं को पाठ्य क्रमों में सम्मिलित किया जाना आवश्यक है। कार्यक्रम के प्रारम्भ में कोऑपरेटिव बैंक सभापति द्वारा अमर सेनानी के चित्र पर माल्यार्पण एवं उनके समक्ष दीप प्रज्जावालित करके शुभ आरम्भ किया गया। उक्त अवसर पर सेनानी भवन में तमाम बुद्धिजीवी, पत्रकारगण, अधिवक्तागण तथा सेनानी के परिजन उपस्थित रहें, और उन्होंने अपनी–अपनी श्रद्धाजंलि सेनानी को अर्पित की। उक्त कार्यक्रम में प्रमुख रूप से रणधीर सिंह, अश्वनी प्रताप सिंह मधुर, राकेश वैद एडवोकेट, राजेन्द्र प्रसाद तिवारी, रामानन्द चौहान, बलवन्त सिंह व सेनानी पुत्र राम मोहन अग्रहरि, सूरज मोहन अग्रहरि एवं पौत्रगण हरि मोहन, आदित्य मोहन सहित श्रद्धाजंलि देने वालो में सेनानी सुरेन्द्र नाथ के वंशज राम मोहन, हरि मोहन, बृज मोहन, अवि मोहन, सतीश मोहन, अजय मोहन, दिव्य मोहन, आदित्य मोहन, हरि कृष्ण मोहल, अंकित मोहन, शिव शंकर अग्रहरी, अपूर्व मोहन, रिशू मोहन, नन्द किशोर अग्रहरी, अरूण कुमार अग्रहरी (पप्पू), पवन गुप्ता, मुकेश अग्रहरी, करमजीत सिंह, सुनील अग्रहरी, पंकज अग्रहरी, शशीधर पाण्डेय, तरूण गुप्ता, आदि गणमान्य व्यक्ति रहें। कार्यक्रम के अन्त में सेनानी पुत्र राममोहन अग्रहरि ने डॉ0 सुरेन्द्र नाथ अग्रहरि को अपनी श्रद्धाजंलि अर्पित करते हुए कार्यक्रम के समापन की घोषणा की।

मरणोपरांत मेजर ध्यानचंद को मिले भारत रत्न - प्रो. आशीष प्रताप सिंह

अयोध्या। हॉकी के जादूगर एवं महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद जी की जयंती के अवसर पर शनिवार को जिला चिकित्सालय, अयोध्या स्थित ब्लड बैंक में वृहद रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का आयोजन मेजर ध्यानचंद खेल उत्थान समिति के तत्वावधान में किया गया। शिविर का शुभारंभ मुख्य अतिथि डॉ. राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या के क्रीड़ा सचिव प्रो. आशीष प्रताप सिंह ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर उन्होंने रक्तदाताओं का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि रक्त का कोई विकल्प नहीं है। रक्तदान से बढ़कर कोई नेक और पुनीत कार्य नहीं हो सकता। इसकी वास्तविक अहमियत तब समझ में आती है, जब किसी अपने को जीवन बचाने के लिए रक्त की आवश्यकता होती है। उन्होंने कहा कि मेजर ध्यानचंद भारतीय खेल जगत के गौरव हैं। उन्होंने अपने अद्भुत खेल कौशल से भारत को विश्व पटल पर गौरवान्वित किया और ओलंपिक खेलों में देश के लिए स्वर्ण पदक जीतकर भारतीय हॉकी को नई पहचान दिलाई। उन्होंने भारत सरकार से मांग की कि हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जाए, जिससे देश के महानतम खिलाड़ियों में से एक को उचित राष्ट्रीय सम्मान मिल सके। समिति के अध्यक्ष आकाश गुप्ता ने कहा कि मेजर ध्यानचंद खेल उत्थान समिति खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के साथ–साथ लगातार जनहित एवं सामाजिक सेवा के कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि मेजर ध्यानचंद जी को भारत रत्न देने की मांग को लेकर राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री को स्पीड पोस्ट के माध्यम से पत्र भी प्रेषित किया गया है। समिति के महासचिव विजय वर्मा एवं लोको पायलट संजय यादव ने कहा कि संस्था का मुख्य उद्देश्य जरूरतमंद मरीजों को समय पर रक्त उपलब्ध कराकर उनका जीवन बचाना है। इसी उद्देश्य से संस्था द्वारा निरंतर रक्तदान शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, ताकि किसी भी मरीज अथवा उसके परिजन को रक्त के लिए परेशान न होना पड़े। शिविर में रक्तदाताओं ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए रक्तदान किया। कार्यक्रम के समापन पर सभी रक्तदाताओं को प्रमाणपत्र एवं स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया।

धोखा देकर कोर्ट से स्टे लेने के मामले में रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश

अयोध्या। धोखा देकर कोर्ट से स्टे आदेश प्राप्त करने के मामले में कोर्ट ने आरोपी सुशील चतुर्वेदी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करके विवेचना करने का आदेश कोतवाली नगर के प्रभारी को दिया है यह आदेश अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन आशुतोष सिंह की अदालत से हुआ है। अधिवक्ता एखलाक अहमद तथा श्रवण यादव ने बताया कि साधना तिवारी निवासी फ्रेंड्स कॉलोनी थाना फ्रेंड्स कॉलोनी जिला इटावा के साथ प्लाट देने के नाम पर ठगी हुई थी। इस पर उन्होंने सुशील चतुर्वेदी तथा उनकी पत्नी ममता जायसवाल सहित पांच लोगों के खिलाफ करीब 10 करोड रुपए ठगी की रिपोर्ट लिखाई थी। दोनों के खाते में 2 करोड़ 45 लाख 38877 रुपए जमा था। इस रकम में से एक करोड़ 90 लाख रुपए अवमुक्त कर साधना तिवारी के खाते में ट्रांसफर किए जाने के लिए न्यायालय से 22 जनवरी 2026 को आदेश हुआ था। इस आदेश को सुशील चतुर्वेदी ने रिट याचिका के माध्यम से उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी लेकिन वहां से कोई स्टे का आदेश नहीं पारित हो सका। जिस पर इस तथ्य को छुपाते हुए सुशील ने जिला जज के न्यायालय में निगरानी शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत किया और धोखे से आदेश दिनांक 22 जनवरी 2026 के विरुद्ध अंतरिम स्टे आदेश भी प्राप्त कर लिया। आरोप है कि उसी दिन उच्च न्यायालय लखनऊ में उपस्थित होकर फोटो भी खिंचवाया। इसी मामले में कोर्ट ने सुशील जायसवाल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करके विवेचना करने का आदेश दिया है।

अवध विवि में हुई प्लेसमेंट ड्राइव, पत्रकारिता के विद्यार्थियों ने दिखाई प्रतिभा

अयोध्या। डॉ. राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. बिजेन्द्र सिंह के कुशल मार्गदर्शन में जनसंचार एवं पत्रकारिता विभाग में राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र की ओर से प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन किया गया। ड्राइव के प्रथम चरण में आयोजित लिखित परीक्षा में बी.वॉक. एवं एमए जनसंचार एवं पत्रकारिता के विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक प्रतिभाग कर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। विभाग के समन्वयक प्रो. अनूप कुमार ने बताया कि राष्ट्रीय समाचार पत्र जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान का कैंपस प्लेसमेंट विद्यार्थियों के लिए अपनी क्षमता को राष्ट्रीय स्तर के मीडिया मंच पर प्रदर्शित करने का महत्वपूर्ण अवसर है। उन्होंने कहा कि इससे विद्यार्थियों में रोजगारपरक कौशल के साथ–साथ व्यावहारिक पत्रकारिता की समझ भी विकसित होगी। चयन प्रक्रिया में विद्यार्थियों की हिंदी भाषा पर पकड़, लेखन क्षमता, समसामयिक विषयों की समझ एवं पत्रकारिता संबंधी दक्षता का आकलन किया जाएगा। चयनित विद्यार्थियों को छह माह का प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा। प्लेसमेंट संयोजक डॉ. विजयेन्दु चतुर्वेदी ने बताया कि विभाग विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयासरत है। मीडिया हाउस का प्लेसमेंट ड्राइव विद्यार्थियों के लिए मीडिया उद्योग की अपेक्षाओं को समझने और अपनी योग्यता को परखने का महत्वपूर्ण मंच है। उन्होंने विद्यार्थियों से चयन प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में आत्मविश्वास एवं पूरी गंभीरता के साथ प्रतिभाग करने का आह्वान किया। इस अवसर पर विभाग के शिक्षक डॉ. आरएन पांडेय, क्षितिज द्विवेदी, एवं विशाल तिवारी उपस्थित रहे।

सान्ध्य हिन्दी दैनिक देश की उपासना

स्वात्वाधिकारी में. प्रभुदयाल प्रकाशन की ओर से श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक द्वारा देश की उपासना प्रेस, उपासना भवन, धर्मसारी, प्रेमापुर, जौनपुर उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं प्रकाशित।

सम्पादक

श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव

मो0 – 7007415808, 9415034002

Email - deshkiupasanadailynews@gmail.com

समाचार–पत्र से संबंधित समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जौनपुर न्यायालय होगा।